रिपोर्ट करने योग्य

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

2002 की सिविल अपील संख्या 1134-1135

उत्तरांचल राज्य .. अपीलकर्ता

बनाम

बलवंत सिंह चौफाल और अन्य .. प्रतिवादी

निर्णय

दलवीर भंडारी, जे.

1. ये अपीलें उत्तरांचल राज्य (अब उत्तराखंड) द्वारा सिविल विविध रिट याचिका संख्या 2001 का 689 (एम/बी) में उत्तरांचल उच्च न्यायालय, नैनीताल की खंडपीठ द्वारा पारित दिनांक 12.7.2001 और 1.8.2001 के आदेशों के विरुद्ध दायर की गई हैं।

2. एल. पी. नैथानी की नियुक्ति को एक जनहित याचिका में उच्च न्यायालय के समक्ष इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि वह संविधान के अनुच्छेद 217 के साथ पढ़े गए अनुच्छेद 165 के मद्देनजर उत्तराखंड के महाधिवक्ता के प्रतिष्ठित पद पर नहीं रह सकते। प्रतिवादी के अनुसार, श्री नैथानी महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य थे क्योंकि महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त होने से बहुत पहले उन्होंने 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली थी। उच्च न्यायालय ने याचिका पर विचार किया और राज्य सरकार को

15 दिनों के भीतर उठाए गए मुद्दे पर निर्णय लेने और उच्च न्यायालय को अवगत कराने का निर्देश दिया।

3. उत्तरांचल राज्य ने 6.8.2001 को इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिकाएँ दायर कीं। इस न्यायालय ने दिनांक 9.8.2001 के आदेश द्वारा उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी। इसके बाद 11.2.2002 को इस न्यायालय ने अनुमति दे दी और निर्देश दिया कि पहले से दिया गया स्टे जारी रहेगा।

4. यह उल्लेख करना उचित होगा कि, नोटिस की तामील के बावजूद, जिन उत्तरदाताओं ने शुरू में महाधिवक्ता के रूप में नैथानी की नियुक्ति को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की थी, वे इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। यह स्पष्ट रूप से याचिका दायर करने में उत्तरदाताओं की गैर-गंभीरता और गैर-प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

5. इससे पहले कि हम इस मामले में शामिल विवाद की जांच करने के लिए आगे बढ़ें, हम महाधिवक्ता के पद और संविधान में इस पद पर नियुक्ति के लिए योग्यताओं से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 165 और 217 को निर्धारित करना उचित समझते हैं। अनुच्छेद 165 जो राज्यों के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति से संबंधित है, उसे निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

> "165. राज्य के महाधिवक्ता. - (1) प्रत्येक राज्य का राज्यपाल, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा ।
>
> (2) महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह उस राज्य की सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो

राज्यपाल उसको समय-समय पर निर्देशित करे या सौंपे और उन कृत्यों का निर्वहन करे जो उसको इस संविधान अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किये गये हों।

(3) महाधिवक्ता, राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राज्यपाल अवधारित करे।

6. अनुच्छेद 217 जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और कार्यालय की शर्तों से संबंधित है, निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

217- उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें.- (1) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से, उस राज्य के राज्यपाल से और मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात्, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा और वह न्यायाधीश अपर या कार्यकारी न्यायाधीश की दशा में अनुच्छेद 224 में उपबंधित रूप से पद धारण करेगा और अन्य दशा में तब तक पद धारण करेगा जब तक वह बासठ वर्ष की आयु प्राप्त नही कर लेता है।

परंतु –

(क) कोई न्यायाधीश, राष्ट्रपति को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा;

(ख) किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए अनच्छेद 124 के खंड (4) में उपबंधित रीति से उसके पद से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकेगा;

(ग) किसी न्यायाधीश का पद, राष्ट्रपति द्वारा उसे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किये जाने पर या राष्ट्रपति द्वारा उसे भारत के राज्यक्षेत्र में किसी अन्य उच्च न्यायालय को, अंतरित किये जाने पर रिक्त हो जाएगा ।

(2) कोई व्यिक्त, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह भारत का नागरिक है और–

(क) भारत के राज्यक्षेत्र में कम से कम दस वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चूका है ; या

(ख) किसी कसी उच्च न्यायालय का या ऐसे दो या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम दस वर्षों तक अधिवक्ता रहा है;

स्पष्टीकरणः इस खंड के प्रयोजनों के लिए–

(क) भारत के राज्यक्षेत्र में न्यायिक पद धारण करने की अवधि की संगणना करने में वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान कोई व्यक्ति न्यायिक पद धारण करने के पश्चात् किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा है या उसने किसी अधिकरण के सदस्य का पद धारण किया है अथवा संघ या राज्य के अधीन कोई ऐसा पद धारण किया है जिसके लिए विधि का विशेष ज्ञान अपेक्षित है ;

(कक) किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहने की अवधि की संगणना करने में वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने अधिवक्ता होने के पश्चात् न्यायीक पद धारण किया है या किसी अधिकरण के सदस्य का पद धारण किया है अथवा संघ या राज्य के अधीन कोई ऐसा पद धारण किया है जिसके लिए विधि का विशेष ज्ञान अपेक्षित है ;

(ख) भारत के राज्यक्षेत्र में न्यायिक पद धारण करने या किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहने की अवधी की संगणना करने में इस सविंधान के प्रारंभ से पहले की वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने, यथास्थिति, ऐसे क्षेत्र में जो 15 अगस्त, 1947 से पहले भारत शासन अधिनियम, 1935 में परिभाषित भारत में समाविष्ट था, न्यायिक पद धारण किया है या वह ऐसे किसी क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा है ।

(3) यदि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो उस प्रश्न का विनिश्चय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा और राष्ट्रपति का विनिश्चय अंतिम होगा ।

7. उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि अनुच्छेद 165 का पहला खंड इस बात पर जोर देता है कि राज्यपाल किसी ऐसे व्यक्ति को महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त करेगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए योग्यताएँ अनुच्छेद 217 के दूसरे खंड में निर्धारित की गई हैं। यह सच है कि अनुच्छेद

217 का पहला खंड कहता है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश "तब तक पद धारण करेगा जब तक वह 60 वर्ष की आयु प्राप्त नही कर लेता है" (प्रासंगिक समय में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष थी और अब यह 62 वर्ष है)। खण्ड पीठ ने आगे कहा कि वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या इस प्रावधान को योग्यता निर्धारित करने के रूप में या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की अवधि निर्धारित करने के रूप में माना जाए। आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि चूंकि प्रावधान दूसरे खंड में नहीं है, इसलिए इसे मात्र उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की अवधि निर्धारित करने वाला माना जा सकता है। न्यायालय ने आगे कहा कि अनुच्छेद 217 के पहले खंड में अवधि के बारे में प्रावधानों को महाधिवक्ता पर लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि संविधान में अनुच्छेद 165 के तीसरे खंड में महाधिवक्ता की नियुक्ति की अवधि के बारे में एक विशिष्ट प्रावधान है जो कहता है कि महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त पद पर बने रहेंगे। यह प्रावधान किसी विशेष आयु के संदर्भ में नियुक्ति की अवधि को सीमित नहीं करता है, क्योंकि न्यायाधीश के मामले में, इसमें "जब तक वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता" शब्दों को शामिल करने की अनुमति नहीं है। इसलिए, संविधान में विशिष्ट प्रावधान को बिना किसी सीमा के प्रभावी किया जाना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया जाता है, मान लीजिए कि पचपन वर्ष की आयु में, तो यह मानने का कोई वारंट नहीं है कि बासठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उसे अपना पद छोड़ना होगा क्योंकि अनुच्छेद 217 के प्रथम खंड में किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में ऐसा कहा गया है। यदि यह सही स्थिति है, जैसा कि हम मानते हैं, तो नियुक्ति खराब नहीं है

क्योंकि व्यक्ति बासठ वर्ष से अधिक का हो चुका है, जब तक कि उसके पास अनुच्छेद 217 के दूसरे खंड में निर्धारित योग्यताएं हैं।

8. उत्तराखंड राज्य की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दिनेश द्विवेदी ने कहा कि, आधी सदी से भी पहले, जी. डी. करकरे बनाम टी. एल. शेवड़े और अन्य एआईआर 1952 नागपुर 330 मामले में, इस विवाद का निपटारा नागपुर उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा किया गया था। और उक्त निर्णय को इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा एटलस साइकिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड सोनीपत बनाम देयर वर्कमेन 1962 सप्प (3) एससीआर 89 के मामले में अनुमोदित किया गया था। करकरे के मामले (ऊपर) में, यह निम्नानुसार देखा गया थाः

> "25. यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से संबंधित सभी प्रावधान महाधिवक्ता पर लागू नहीं किये जा सकते। दोनों कार्यालयों के लिए पारिश्रमिक के प्रावधान अलग-अलग हैं। उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश अनुच्छेद 221 द्वारा शासित होता है। महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 के खंड (3) द्वारा शासित होता है और राज्यपाल द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त करता है।
>
> 26. अनुच्छेद 165 का पहला खंड इस बात पर जोर देता है कि राज्यपाल, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए योग्यताएँ अनुच्छेद 217 के दूसरे खंड में निर्धारित की गई हैं। यह सच है कि अनुच्छेद 217 का पहला खंड कहता है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश "तब तक पद धारण

करेगा जब तक वह बासठ वर्ष की आयु प्राप्त नही कर लेता"। असली सवाल यह है कि क्या इस प्रावधान को योग्यता निर्धारित करने वाले या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की अवधि निर्धारित करने वाले प्रावधान के रूप में माना जाना चाहिए। चूंकि यह प्रावधान दूसरे खंड में नहीं है, इसलिए इसे केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की अवधि निर्धारित करने वाला प्रावधान माना जा सकता है।

27. अनुच्छेद 217 के पहले खंड में अवधि के बारे में प्रावधान को महाधिवक्ता पर लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि संविधान में अनुच्छेद 165 के तीसरे खंड में महाधिवक्ता की नियुक्ति की अवधि के बारे में एक विशिष्ट प्रावधान है जो कहता है कि महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेगा। चूँकि यह प्रावधान किसी विशेष आयु के संदर्भ में नियुक्ति की अवधि को सीमित नहीं करता है, जैसा कि एक न्यायाधीश के मामले में होता है, इसमें "जब तक वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता" शब्दों को शामिल करने की अनुमति नहीं है। इसलिए संविधान में विशिष्ट प्रावधान को बिना किसी सीमा के प्रभावी किया जाना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त किया जाता है, मान लीजिए पचपन वर्ष की आयु में, तो यह मानने का कोई वारंट नहीं है कि साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उसे अपना पद छोड़ देना चाहिए क्योंकि अनुच्छेद 217 के पहले खंड में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में ऐसा कहा गया है। यदि यह सही स्थिति है, जैसा कि हम मानते हैं, तो नियुक्ति बुरी नहीं है क्योंकि व्यक्ति साठ वर्ष से अधिक का

हो चुका है, जब तक कि उसके पास अनुच्छेद 217 के दूसरे खंड में निर्धारित योग्यताएं हैं। यह सुझाव नहीं दिया गया कि गैर-आवेदक के पास उस खंड में निर्धारित योग्यताएं नहीं हैं।

28. यह प्रावधान कि उच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश "साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पर रहेगा" के दो पहलू हैं। जबकि एक पहलू में इसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त व्यक्ति को साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अच्छे व्यवहार के दौरान कार्यकाल की गारंटी के रूप में देखा जा सकता है, दूसरे पहलू में इसे एक अक्षमता के रूप में देखा जा सकता है जिसमें एक न्यायाधीश साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात अधिकार के रूप में अपना पद धारण नहीं कर सकता है।

29. हम अधिकार के रूप में कहते हैं क्योंकि अनुच्छेद 224 के तहत एक व्यक्ति जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हो गया है, उससे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध किया जा सकता है। इसलिए किसी व्यक्ति द्वारा साठ वर्ष की आयु प्राप्त करना न्यायाधीश के कार्यों को करने के लिए अयोग्यता नहीं माना जा सकता है। लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य व्यक्ति के मामले और अनुच्छेद 224 के तहत न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध करने वाले व्यक्ति के मामले के बीच अंतर करने की कोशिश की।

अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्य व्यक्ति के मामले और अनुच्छेद 224 के तहत बैठने और कार्य करने के लिए अनुरोध किए गए व्यक्ति के मामले के बीच अंतर न्यायाधीश के कार्यों को करने की योग्यता के संबंध में नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 221, 222, 223, आदि द्वारा प्रदान किए गए मामलों के संबंध में है। संविधान की भाषा में साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर एक न्यायाधीश अनुच्छेद 217 के दूसरे खंड में निर्धारित योग्यता खो नहीं देता है। एक व्यक्ति जो उस आयु को प्राप्त कर लेता है उसे न्यायाधीश के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए नहीं कि वह अनुच्छेद 217 के दूसरे खंड के अर्थ के तहत नियुक्त होने के लिए योग्य नहीं है, बल्कि इसलिए कि उस अनुच्छेद का पहले खंड में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि एक न्यायाधीश तब तक पद पर बना रहेगा जब तक वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है।

(30) यदि अनुच्छेद 217 के पहले खंड में प्रावधान को साठ वर्ष की आयु तक कार्यालय के कार्यकाल की गारंटी के रूप में देखा जाता है, तो यह महाधिवक्ता के लिए उपलब्ध नहीं है क्योंकि वह राज्यपाल प्रसादपर्यन्त पद धारण करता है, हमें कोई बाध्यकारी कारण नहीं दिखता कि विकलांगता के रूप में समझा जाने वाला वही प्रावधान उस पर क्यों लागू किया जाना चाहिए। इसलिए, हमारा विचार है कि अनुच्छेद 217 के पहले खंड को अनुच्छेद 165 के पहले खंड के साथ नहीं पढ़ा जा सकता है, जिससे किसी व्यक्ति को साठ वर्ष की आयु के पश्चात महाधिवक्ता नियुक्त होने से अयोग्य ठहराया जा सके।

हमें इस मुद्दे पर कोई संदेह नहीं है। भले ही प्रश्न को संदेह से मुक्त न माना जाए, क्योंकि आवेदक अनुच्छेद 217 के पहले खंड को गैर-आवेदक के विरुद्ध अक्षम करने वाले प्रावधान के रूप में समझना चाहता है, हम यह नहीं भूल सकते कि विकलांगता वाले प्रावधानों को सख्ती से समझा जाना चाहिए: 'परमेश्वरम पिल्लई भास्कर पिल्लई बनाम राज्य', 1950-5 डोम एल आर (ट्रैव) 382। प्रिवी काउंसिल के आधिपत्य द्वारा अनुमोदित निर्माण का सिद्धांत यह है कि यदि अक्षम करने वाले प्रावधान के अर्थ के बारे में कोई अस्पष्टता है, तो जो निर्माण व्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में है, उसे प्रभावी बनाया जाना चाहिए: 'डेविड बनाम डिसिल्वा', (1934) एसी 106 प. 114 पर।

(31) इस तर्क में कोई बल नहीं है कि गैर-आवेदक को महाधिवक्ता नियुक्त नहीं किया जा सकता था क्योंकि वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुआ था। विद्वान अधिवक्ता ने हमें संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड (4)(ए) का हवाला दिया और कहा कि संविधान उस व्यक्ति के बीच अंतर करता है जो न्यायाधीश रहा है और जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य है। हमारे विचार में प्रावधान मात्र उन व्यक्तियों के वर्गों की विस्तृत गणना करता है जो एक सलाहकार बोर्ड का गठन कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए या तो योग्यता हो या जरूर रही होगी या जरूर होना चाहिए। इसलिए प्रावधान का इस सवाल पर कोई असर नहीं है कि क्या अनुच्छेद 165 के पहले खंड को अनुच्छेद 217 के पहले

खंड के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जिस प्रश्न का हम पहले ही नकारात्मक उत्तर दे चुके हैं। गैर-आवेदक का मामला अनोखा है। अनुच्छेद 220 उन पर लागू नहीं होता क्योंकि उन्होंने संविधान के लागू होने के पश्चात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद धारण नहीं किया था। इसलिए उस अनुच्छेद में निहित प्रतिबंध भी उनके रास्ते में नहीं आती है।"

9. इस तथ्य के बावजूद कि इस न्यायालय के एक निर्णय से विवाद पूरी तरह से सुलझ गया है, इसे समय-समय पर विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष कई रिट याचिकाओं में उठाया गया है। हम यह प्रदर्शित करने के लिए कुछ निर्णयों को पुन: प्रस्तुत करेंगे कि इस न्यायालय द्वारा विवाद को अंतिम रूप से निपटाए जाने के पश्चात, समान राहत के साथ अंधाधुंध याचिकाएं दायर करने से न्यायिक प्रणाली पर अनावश्यक दबाव पैदा होता है और परिणामस्वरूप वास्तविक और प्रामाणिक मामलों के निपटारे में अत्यधिक देरी होती है।

10. निम्नलिखित मामले यह प्रदर्शित करेंगे कि, इस न्यायालय द्वारा मामला निपटाए जाने के पश्चात कितने उच्च न्यायालयों में इसी तरह का विवाद उठाया गया है:

11. घनश्याम चंद्र माथुर बनाम राजस्थान राज्य और अन्य 1979 साप्ताहिक कानून नोट्स 773 में, महाधिवक्ता की नियुक्ति को एक बार फिर चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने कहा कि "...भारत के संविधान के अनुच्छेद 165 में सेवानिवृत्ति की कोई आयु का उल्लेख नहीं किया गया है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि सेवानिवृत्ति की आयु जो

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर लागू होती है, वह महाधिवक्ता के कार्यालय पर लागू नहीं होती है।

12. डॉ. चन्द्रभान सिंह बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य एआईआर 1983 राज. 149 में महाधिवक्ता की नियुक्ति की वैधता संबंधी प्रश्न को चुनौती दी गयी थी। इस मामले में न्यायालय ने माना था कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु महाधिवक्ता के पद पर लागू नहीं होती है। न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए संविधान में पारिश्रमिक और कार्यालय के कार्यकाल जैसे सभी प्रावधान महाधिवक्ता के पद पर लागू नहीं होते हैं।

13. मनेन्द्र नाथ राय एवं अन्य बनाम वीरेन्द्र भाटिया एवं अन्य एआईआर 2004 ऑल 133 में, महाधिवक्ता की नियुक्ति को एक बार फिर चुनौती दी गई। न्यायालय ने निम्नानुसार कहा:

> "यह तर्क कि महाधिवक्ता की नियुक्ति के मामले में संविधान के अनुच्छेद 217 के उप-खंड (1) के प्रावधान का पालन किया जाना चाहिए, पूरी तरह से गलत है। संविधान का अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद की नियुक्ति और शर्तों से संबंधित है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में राज्य के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श को महाधिवक्ता की नियुक्ति के मामले में आवश्यकता नहीं बनाया जा सकता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति उपरोक्त अनुच्छेद द्वारा शासित नहीं है जो संविधान के अध्याय-V भाग-6 में आता है जबकि अनुच्छेद 165, जो राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति से संबंधित है, भाग 6 के अध्याय II में आता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति के साथ-

साथ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए संविधान की योजना पूरी तरह से अलग है।"

14. 2005 की रिट याचिका संख्या 716 (एम/बी) 2005 (3) ईएससी 2001 में प्रेम चंद्र शर्मा और अन्य बनाम मिलन बनर्जी और अन्य के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 4.2.2005 के खण्ड पीठ के फैसले में, भारत के लिए अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति को चुनौती दी गई थी और यथास्थिति अधिकार पृच्छा प्रकृति में एक रिट जारी करने के लिए प्रार्थना की गई थी, क्योंकि याचिकाकर्ता के अनुसार, प्रतिवादी मिलन बनर्जी पहले ही 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके थे और उन्हें भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता था। उस मामले में, खण्ड पीठ ने जी.डी. करकरे के मामले (उपरोक्त) में नागपुर उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के फैसले पर भरोसा किया। न्यायालय ने निम्नानुसार कहा:

> "संविधान के विभिन्न प्रावधानों की जांच करने के बाद, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत का संविधान विभिन्न संवैधानिक नियुक्तियों की सेवानिवृत्ति की आयु प्रदान नहीं करता है। राज्य में अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल और एडवोकेट जनरल की नियुक्ति के लिए कोई बाहरी आयु सीमा प्रदान नहीं की गई है। हमारे देश में प्रचलित लोकतांत्रिक व्यवस्था में अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और परंपरागत रूप से वह प्रधानमंत्री के साथ ही इस्तीफा दे देता है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील अटॉर्नी जनरल की सेवानिवृत्ति की आयु या अटॉर्नी जनरल के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति पर संविधान में दिए गए प्रतिबंध से संबंधित कोई कानून नहीं दिखा सके, जो पहले ही 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है।

हमारी सुविचारित राय है कि जहां तक अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति का सवाल है, संविधान के अक्षर और भावना, पद की महत्ता, उत्तरदायित्व और उच्च स्थिति को देखते हुए, यह बार के सदस्य को भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त होने के लिए कुछ आवश्यकताएँ निर्धारित करता है। यह इस पृष्ठभूमि में है कि संविधान निर्माताओं ने न्यूनतम अपेक्षित योग्यता निर्धारित करना आवश्यक समझा, जिसमें कहा गया कि जो व्यक्ति माननीय न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य है। भारत के अटॉर्नी-जनरल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। हालाँकि, यह स्थिति हमें किसी भी हद तक इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा सकती कि अटॉर्नी जनरल 65 वर्ष की आयु के बाद अपना पद नहीं संभाल सकते। जैसा कि यहां ऊपर बताया गया है, ऐसे कई संवैधानिक पदाधिकारी हैं जहां पद संभालने के लिए कोई बाहरी आयु सीमा प्रदान नहीं की गई है।"

15. उपरोक्त निर्णयों में कानून की स्पष्ट व्याख्या के मद्देनजर, यह विवाद पूरी तरह से सुलझ गया है कि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात की जा सकती है। इसी प्रकार, भारत के अटॉर्नी जनरल को 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद नियुक्त किया जा सकता है। अन्य प्राधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में कई अन्य मामलों में, न्यायालयों ने लगातार समान दृष्टिकोण अपनाया है।

16. इस न्यायालय ने बिनय कांत मणि त्रिपाठी बनाम भारत संघ और अन्य (1993) 4 एससीसी 49 में इस स्थिति की फिर से पुष्टि की है। कोर्ट ने कहा कि डी.के. की नियुक्ति का निर्णय अग्रवाल को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त करना

इस आधार पर अवैध या गलत नहीं ठहराया जा सकता कि उनकी उम्र बासठ वर्ष से अधिक है।

17. बैष्णब पटनायक और अन्य बनाम राज्य एआईआर 1952 उड़ीसा 60 में, निवारक निरोध अधिनियम के तहत सलाहकार बोर्ड में एक व्यक्ति की नियुक्ति को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि वह 60 वर्ष (उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए उस समय सेवानिवृत्ति की आयु) से अधिक उम्र का था। न्यायालय ने बताया:

> "अगर संविधान निर्माताओं ने सोचा कि आयु सीमा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताओं में से एक है, तो उन्होंने इसे अनुच्छेद 217 के खंड (1) में निर्दिष्ट नहीं किया होता, बल्कि इसे उक्त अनुच्छेद के खंड (2) में शामिल किया होता।"

18. गुरपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य (2005) 5 एससीसी 136 में, नीलामी रिकॉर्डर के रूप में अपीलकर्ता की नियुक्ति को चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने माना कि जनहित याचिका के रूप में याचिका पर विचार करने की गुंजाइश और विशेष रूप से किसी कर्मचारी की सेवा से जुड़े मामलों में याचिकाकर्ता की अधिस्थिति की जांच इस न्यायालय द्वारा विभिन्न मामलों में की गई है। न्यायालय ने कहा कि याचिका पर विचार करने से पहले, न्यायालय को (ए) आवेदक की साख के बारे में संतुष्ट होना चाहिए; (बी) उसके द्वारा दी गई जानकारी की प्रथम दृष्टया सत्यता या प्रकृति; (सी) जानकारी अस्पष्ट और अनिश्चित नहीं है। जानकारी में गंभीरता और संजीदगी शामिल होनी चाहिए। न्यायालय को दो परस्पर विरोधी हितों के बीच संतुलन बनाना होगा; (i) किसी को भी दूसरों के चरित्र को धूमिल करने वाले बेतुके और लापरवाह आरोपों में शामिल होने

की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए; और (ii) सार्वजनिक शरारत से बचना और परोक्ष उद्देश्यों के लिए उचित कार्यकारी कार्रवाइयों पर हमला करने की मांग करने वाली शरारती याचिकाओं से बचना चाहिए।

19. उपरोक्त मामले हमें स्पष्ट रूप से यह तस्वीर देते हैं कि कैसे समय-समय पर न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग किया गया है और इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा विवाद को अंततः निपटाए जाने के पश्चात, विभिन्न न्यायालयों में बार-बार याचिकाएँ दायर की गईं।

20. मौजूदा मामले में, उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं में से एक न्यायालय का प्रैक्टिसिंग अधिवक्ता है। उन्होंने इस मामले में हाई कोर्ट के असाधारण क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल किया है। महान पेशे के एक माननीय सदस्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह ऐसे मामले में न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल न करें, जहां विवाद अब अस्तित्व में नहीं है।

21. इसी तरह, यह सुनिश्चित करना न्यायालय का बाध्यकारी कर्तव्य है कि एक बार आधिकारिक निर्णय द्वारा निपटाए गए विवाद को फिर से नहीं खोला जाना चाहिए जब तक कि ऐसा करने के लिए असाधारण कारण न हों।

22. वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने इस तथ्य के बावजूद याचिका पर विचार किया कि मामले में शामिल विवाद अब अछूता नहीं रह गया है। उस रिट याचिका के जवाब में, उत्तराखंड के मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने भी उच्च न्यायालय के समक्ष एक विविध आवेदन दायर किया। आवेदन का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

> "3. संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत नियुक्त किए गए निम्नलिखित अटॉर्नी जनरलों को जब अटॉर्नी जनरल के रूप

में नियुक्त किया गया था, तब उनकी नियुक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित आयु से अधिक थी।

(I) श्री एम. सी. सीतलवाड़

(II) श्री सी. के. दपातरी

(III) श्री निरेन डे

(IV) श्री लाल नारायण सिंह

(V) श्री के. परासरन

(VI) श्री सोली सोराबजी

4. वर्तमान अटॉर्नी जनरल (श्री मिलन बनर्जी) की नियुक्ति को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी और याचिका को तुरंत खारिज कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता श्री आर. पी. गोयल, जिनकी नियुक्ति के समय 62 वर्ष की आयु हो चुकी थी, की नियुक्ति भी खारिज कर दी गई।

5. कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में श्री जे.वी. के.एस. चौधरी, सर ऋषिराम, पं. कन्हैया लाल मिश्रा, श्री शांति स्वरूप भटनागर और कई अन्य लोगों को 62 वर्ष की आयु पार करने के बाद महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया था। भारत में ऐसे कई महाधिवक्ता हुए जिनकी नियुक्ति 62 साल के बाद हुई ।"

23. कुछ वर्ष पहले उत्तराखंड राज्य यूपी राज्य का हिस्सा था। उत्तर प्रदेश राज्य में, बड़ी संख्या में नियुक्त किए गए महाधिवक्ता उनकी नियुक्ति के समय 62 वर्ष से अधिक आयु के थे। याचिकाकर्ता, एक स्थानीय प्रैक्टिसिंग अधिवक्ता, को संविधान के अनुच्छेद 226 के

तहत जनहित में इस रिट याचिका को दायर करने से पहले कुछ सावधानी बरतनी चाहिए थी।

24. इस मामले में याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए विवाद का फैसला 58 साल पहले करकरे (उपरोक्त) के फैसले में किया गया था, जिसे 1962 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने मंजूरी दे दी थी। दुर्भाग्य से यही विवाद समय-समय पर विभिन्न उच्च न्यायालयों में बार-बार उठाया जाता रहा है। जब विवाद अब अछूता मामला नहीं रहता है और एक ही विवाद बार-बार उठाया जाता है, तो यह न केवल न्यायालय का बहुमूल्य समय बर्बाद करता है और न्यायालय को अन्य योग्य मामलों पर निर्णय लेने से रोकता है, बल्कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक पद और उस पद पर नियुक्त व्यक्ति को नीचा दिखाने की अपार क्षमता भी रखता है।

25. हमारे सुविचारित दृष्टिकोण में, यह जनहित याचिका के नाम पर न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग का एक स्पष्ट मामला है। इस प्रवृत्ति को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए, अब इस उम्मीद में एक आधिकारिक निर्णय द्वारा जनहित याचिका के सभी जुड़े मुद्दों की जांच करना अनिवार्य हो गया है कि भविष्य में ऐसी कोई याचिका दायर नहीं की जाएगी और/या न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

26. विवाद को निपटाने के लिए, हम विभिन्न देशों में जनहित याचिका की विभिन्न परिभाषाओं से निपटना उचित मानते हैं। हम जनहित याचिका के विकास की भी जांच करेंगे।

<u>जनहित याचिका की परिभाषाएँ</u>

27. जनहित याचिका को परिभाषित किया गया है ब्लैक लॉ डिक्शनरी (छठा संस्करण) निम्नानुसार हैः - "सार्वजनिक हित कुछ ऐसा

जिसमें जनता या समुदाय के एक वर्ग की आर्थिक रुचि या कुछ हित है और जिसके द्वारा उनके कानूनी अधिकार या दायित्व प्रभावित होतें हैं। इसका मतलब महज़ जिज्ञासा जितना संकीर्ण कुछ भी नहीं है, या विशेष इलाकों के हितों के रूप में, जो विचाराधीन मामलों से प्रभावित हो सकते हैं। आम तौर पर स्थानीय, राज्य या राष्ट्रीय सरकार के मामलों में नागरिकों द्वारा साझा की जाने वाली रुचि .... ”

28. एडवांस्ड लॉ लेक्सिकन ने 'जनहित याचिका' को निम्नानुसार परिभाषित किया हैः-

> 'पी. आई. एल " शब्द का अर्थ है सार्वजनिक हित के प्रवर्तन के लिए कानून की न्यायालय में शुरू की गई एक कानूनी कार्रवाई या सामान्य रुचि जिसमें जनता या समुदाय के एक वर्ग की आर्थिक रुचि या कुछ हित है और जिसके द्वारा उनके कानूनी अधिकार या दायित्व प्रभावित होतें हैं।

”29. संयुक्त राज्य अमेरिका में फोर्ड फाउंडेशन द्वारा स्थापित लोक हित कानून के लिए परिषद ने लोक हित कानून, संयुक्त राज्य अमेरिका, 1976 की अपनी रिपोर्ट में "जनहित याचिका" को निम्नानुसार परिभाषित किया है:

> “जनहित कानून वह नाम है जो हाल ही में प्रयासों के लिए दिया गया है, जो पहले से अप्रभावित समूहों और हितों को कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। इस तरह के प्रयास इस मान्यता में किए गए हैं कि कानूनी सेवाओं के लिए साधारण बाजार स्थान आबादी के महत्वपूर्ण वर्गों और महत्वपूर्ण हितों के लिए ऐसी सेवाएं प्रदान करने में विफल रहता है। इस तरह के समूहों और हितों में उचित पर्यावरणविद्, उपभोक्ता,

नस्लीय और जातीय अल्पसंख्यक और अन्य शामिल हैं।" (मेसर्स होलिको पिक्चर्स प्रा. लिमिटेड बनाम प्रेम चंद्र मिश्रा & अन्य - एआईआर 2008 एससी 913, पैरा 19)।

30. इस न्यायालय ने पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स एंड अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड अन्य (1982) 3 एस. सी. सी. 235 में 'जनहित याचिका' को परिभाषित किया और कहा कि जनहित याचिका याचिकाकर्ता, सार्वजनिक प्राधिकरण राज्य और न्यायपालिका द्वारा संवैधानिक या बुनियादी नियमों का पालन करने के लिए एक सहयोगी या सहयोगात्मक प्रयास है जो संवैधानिक या बुनियादी मानवाधिकारों, लाभों और विशेषाधिकारों के गरीब, दलित और कमजोर वर्गों के लिए सुरक्षित है।

<u>जनहित याचिका की उत्पत्ति:</u>

31. जनहित याचिका न्यायालय के संवैधानिक दायित्व की प्राप्ति का उत्पाद है।

32. ये सभी याचिकाएँ जनहित याचिका के बड़े बैनर के तहत दायर की जाती हैं। मामले के इस दृष्टिकोण में, यह जांचना अनिवार्य हो गया है कि जनहित याचिका की रूपरेखा क्या हैं? जनहित याचिका की उपयोगिता और महत्व क्या है? क्या इसी तरह का अधिकार क्षेत्र अन्य देशों में मौजूद है या यह एक स्वदेशी रूप से विकसित न्यायशास्त्र है? हमारे देश में प्रचलित विशेष स्थितियों को देखते हुए, क्या जनहित याचिका को न्यायालयों द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए या हतोत्साहित किया जाना चाहिए? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका हम इस निर्णय में उत्तर देने का प्रयास करेंगे।

33. हमारी राय के अनुसार, जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण

क्षेत्राधिकार है। कई मामलों में न्यायालयों ने महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं और आदेश पारित किए हैं जिन्होंने देश में सकारात्मक बदलाव लाए हैं। न्यायालयों के निर्देशों ने कई मामलों में समाज के हाशिए के वर्गों को बेहद लाभान्वित किया है। इसने पारिस्थितिकी, पर्यावरण, वन, समुद्री जीवन, वन्यजीवों आदि के सुरक्षा और संरक्षण में भी मदद की है। कुछ हद तक न्यायालय के निर्देशों ने सार्वजनिक जीवन में संभावना और पारदर्शिता बनाए रखने में मदद की है।

34. न्यायिक समीक्षा के अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए इस न्यायालय ने महसूस किया कि अत्यधिक गरीबी, अज्ञानता, भेदभाव और अशिक्षा के कारण समाज के एक बहुत बड़े हिस्से को प्राचीन काल से न्याय से वंचित किया गया था और वास्तव में उनके पास न्याय तक कोई पहुंच नहीं है। प्रमुख रूप से, समाज के गरीब, वंचित, असुरक्षित, भेदभावपूर्ण और हाशिए के वर्गों को न्याय प्रदान करने के लिए, इस न्यायालय ने जनहित याचिका को शुरू किया, प्रोत्साहित और प्रेरित किया। यह मुक़दमा इस न्यायालय की अपने कर्तव्य और संवैधानिक दायित्व को पूरा करने की गहरी और गहन इच्छा का परिणाम है।

35. उच्च न्यायालयों ने इस न्यायालय का अनुसरण किया और संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत समान क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया। न्यायालयों ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के अर्थ का विस्तार किया। अधिस्थिति के नियम को कमजोर कर दिया गया और समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को न्याय तक पहुंच प्रदान करने के लिए 'पीड़ित व्यक्ति' के पारंपरिक अर्थ को व्यापक बनाया गया, जिसे अन्यथा न्यायिक प्रणाली से कोई लाभ नहीं मिल रहा था। हम इसे जनहित

याचिका का प्रथम चरण या स्वर्ण युग की संज्ञा देना चाहेंगे। हम 'पीड़ित व्यक्ति' की परिभाषा को व्यापक बनाने के पश्चात पहले चरण में इस न्यायालय द्वारा तय किए गए महत्वपूर्ण मामलों पर संक्षेप में विचार करेंगे। हम उन मामलों से भी निपटेंगे कि इस न्यायालय ने जनहित याचिका के किसी भी दुरुपयोग को कैसे रोका?

36. अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ (रेलवे) बनाम भारत संघ और अन्य एआईआर 1981 एससी 298 पृष्ठ 317 में इस न्यायालय ने माना कि हमारी वर्तमान प्रक्रियात्मक न्यायशास्त्र व्यक्तिवादी एंग्लो-इंडियन साँचे में नहीं है। यह व्यापक-आधारित और जन-उन्मुख है, और 'वर्ग कार्रवाई', 'जनहित याचिका' और 'प्रतिनिधि कार्यवाही' के माध्यम से न्याय तक पहुंच की कल्पना करता है। वास्तव में, बड़ी संख्या में छोटे भारतीय मुकदमेबाजी की महंगी बहुलता के बजाय सामूहिक कार्यवाही के माध्यम से न्यायालयों में उपचार की मांग कर रहे हैं, जो हमारे लोकतंत्र में सहभागी न्याय की पुष्टि है। हमें यह मानने में कोई झिझक नहीं है कि 'वाद हेतुक', 'पीड़ित व्यक्ति' और व्यक्तिगत मुकदमेबाजी की संकीर्ण अवधारणाएं कुछ न्यायालयों में अप्रचलित होती जा रही हैं।

37. बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ और अन्य एआईआर 1984 एससी 802 के मामले में, इस न्यायालय ने अति-दलितों या उसके सदस्यों के हितों का समर्थन करने वाले गैर-पंजीकृत संघ की भी एक याचिका पर विचार किया, जिसमें कहा गया था कि "छोटे भारतीयों" के मुद्दे का समर्थन कोई भी व्यक्ति कर सकता है जिसकी इस मामले में कोई रुचि नहीं है।

38. उक्त मामले में, इस न्यायालय ने आगे कहा कि जहां एक जनहित याचिका यह आरोप लगाती है कि कुछ श्रमिक बंधन में और

अमानवीय परिस्थितियों में रह रहे हैं, तो सरकार से यह उम्मीद नहीं की जाती है कि वह प्रारंभिक आपत्ति उठाए कि याचिकाकर्ताओं या उन श्रमिकों के किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है जिनकी ओर से याचिका दायर की गई है। इसके विपरीत, सरकार को न्यायालय द्वारा जांच का स्वागत करना चाहिए, ताकि यदि यह पाया जा सके कि वास्तव में बंधुआ मजदूर हैं या भले ही श्रमिक बन्धित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 में परिभाषित शब्द के सख्त अर्थ में बंधुआ नहीं हैं लेकिन उनसे जबरन मजदूरी कराई जाती है या पूरी तरह से अभाव और अपमान का जीवन जीने के लिए मजबूर किया जाता है, ऐसी स्थिति को सरकार द्वारा ठीक किया जा सकता है।

39. जनहित याचिका की प्रकृति में नहीं है प्रतिकूल मुकदमा लेकिन यह एक चुनौती और एक अवसर है सरकार और उसके अधिकारियों को बुनियादी मानवाधिकार बनाने के लिए वंचित और कमजोर वर्गों के लिए सार्थक समुदाय और उन्हें सामाजिक और आर्थिक न्याय का आश्वासन देने के लिए यह हमारे संविधान का विशिष्ट भाग है। सरकार और इसके अधिकारियों को जनहित याचिका का स्वागत करना चाहिए क्योंकि यह उन्हें यह जांचने का अवसर प्रदान करेगा कि क्या गरीबों और वंचितों को उनके सामाजिक और आर्थिक अधिकार मिल रहे हैं या क्या वे समुदाय के मजबूत और शक्तिशाली वर्गों के हाथों धोखे और शोषण का शिकार बने रहेंगे और क्या सामाजिक और आर्थिक न्याय उनके लिए एक सार्थक वास्तविकता बन गया है या यह महज एक चिढ़ाने वाला भ्रम और अवास्तविकता का वादा बनकर रह गया है, ताकि जनहित याचिका में शिकायत सही पाए जाने पर वे अपने संवैधानिक दायित्व का

निर्वहन करते हुए शोषण और अन्याय को जड़ से खत्म कर सकें और कमजोर वर्गों को उनके अधिकार और हक़ सुनिश्चित करना।

40. उर्वरक निगम कामागर संघ (विनियमित, सिंदरी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 1981 ए. आई. आर. एस. सी. 844 में, इस न्यायालय ने कहा कि "जनहित याचिका सहभागी न्याय की प्रक्रिया का हिस्सा है और उस स्वरुप के दीवानी मुकदमे में 'अधिस्थति' (*सुने जाने का अधिकार*) का न्यायिक दरवाजे पर उदार स्वागत होना चाहिए।"

41. रामशरण औतनुप्रसी और एक अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 1989 ए. आई. आर. एस. सी. 549 में, इस न्यायालय ने कहा कि जनहित याचिका समुदाय के वंचित और कमजोर वर्गों के लिए बुनियादी मानवाधिकारों को सार्थक बनाने और उन्हें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए है।

<u>भारत में जनहित याचिका का उद्भव</u>

42. भारत में जनहित याचिका की उत्पत्ति और उद्भव न्यायपालिका द्वारा समाज के विशाल वर्गों- गरीबों और समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों के प्रति संवैधानिक दायित्व की प्राप्ति से हुआ। यह अधिकार क्षेत्र न्यायिक रचनात्मकता और शिल्प कौशल द्वारा बनाया और तराशा गया है। एम. सी. मेहता और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य ए. आई. आर. 1987 एस. सी. 1086 में, इस न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 32 इस न्यायालय को केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए निर्देश, आदेश या रिट जारी करने की शक्ति प्रदान नहीं करता है। इसके बजाय, यह लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए इस न्यायालय पर एक संवैधानिक दायित्व भी रखता है। न्यायालय ने जोर देकर कहा कि इस संवैधानिक दायित्व को

साकार करते हुए, "उसके पास सभी आनुषंगिक और सहायक शक्तियां हैं जिनमें नए उपचार बनाने और मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए तैयार की गई नई रणनीतियां तैयार करने की शक्ति शामिल है।" न्यायालय ने महसूस किया कि अत्यधिक गरीबी के कारण समाज का एक बड़ा वर्ग न्यायालय का रुख नहीं कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों का उनके लिए कोई अर्थ नहीं है और न्यायिक नवाचार द्वारा समाज के हाशिए पर पड़े वर्ग के मौलिक अधिकारों को संरक्षित करने और उनकी रक्षा करने के लिए, न्यायालयों ने न्यायिक नवाचार और रचनात्मकता द्वारा जनहित में आवश्यक निर्देश देना और आदेश पारित करना शुरू कर दिया।

43. जनहित याचिका का विकास भारतीय न्यायशास्त्र के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण विकास रहा है। 1970 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों ने समाज के हाशिए पर पड़े और वंचित वर्गों की ओर से जनहित में उत्साही व्यक्तियों, संस्थानों और/या निकायों द्वारा याचिकाएं दायर करने की अनुमति देने के लिए सख्त अधिकार क्षेत्र की आवश्यकताओं को ढीला कर दिया। उच्च न्यायालयों ने संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत उन्हें दी गई व्यापक शक्तियों का प्रयोग किया। जनहित याचिका में न्यायालयों से जिस तरह के उपचार की मांग की जाती है, वह प्रभावित व्यक्तियों और समूहों को उपचार देने से परे है। उपयुक्त मामलों में न्यायालयों ने दिशा-निर्देश और मार्गदर्शन भी दिए हैं। न्यायालयों ने कानून के कार्यान्वयन की निगरानी की है और कानून के अभाव में दिशानिर्देश भी तैयार किए हैं। यदि 70 और 80 के दशक के मामलों का विश्लेषण किया जाए, तो न्यायालयों द्वारा विचार किए गए अधिकांश जनहित याचिका मामले समाज के हाशिए पर

पड़े और वंचित वर्गों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन से संबंधित हैं। इसे भारत में जनहित याचिका का पहला चरण कहा जा सकता है।

44. भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने अधिस्थिति (*सुने जाने का अधिकार*) के पारंपरिक नियम और "व्यथित व्यक्ति" की परिभाषा का विस्तार किया।

45. इस निर्णय में हम जनहित याचिका की उत्पत्ति और विकास पर चर्चा करना चाहेंगे। हम जनहित याचिका को मोटे तौर पर तीन चरणों में विभाजित करना उचित समझते हैं।

चरण-I: यह इस न्यायालय के मामलों से संबंधित है जहां मुख्य रूप से हाशिए पर पड़े समूहों और समाज के उन वर्गों के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए निर्देश और आदेश पारित किए गए थे जो अत्यधिक गरीबी, निरक्षरता और अज्ञानता के कारण इस न्यायालय या उच्च न्यायालयों से संपर्क नहीं कर सकते हैं।

चरण-II: यह सुरक्षा, पारिस्थितिकी का संरक्षण, पर्यावरण, वन, समुद्री जीवन, वन्यजीव, पहाड़, नदियों, ऐतिहासिक स्मारकों आदि से संबंधित मामलों से संबंधित है।

चरण-III: यह शासन में ईमानदारी, पारदर्शिता और अखंडता बनाए रखने के लिए न्यायालयों द्वारा जारी निर्देशों से संबंधित है।

46. इसके बाद, हम जनहित याचिका के दुरुपयोग के पहलुओं और उपचारात्मक उपायों से निपटने का भी प्रस्ताव करते हैं जिनके द्वारा इसके दुरुपयोग को रोका या अंकुश लगाया जा सकता है।

<u>चरण-I के कुछ महत्वपूर्ण मामलों की विवेचना</u>

47. न्यायालय ने जसभाई मोतीभाई देसाई बनाम रोशन कुमार, हाजी बशीर अहमद और अन्य (1976) 1 एस. सी. सी. 671 में "व्यथित व्यक्ति" शब्दों की व्याख्या करते हुए कहा कि "पारंपरिक नियम उन मामलों में लेने के लिए पर्याप्त लचीला है जहां आवेदक किसी कार्य या प्राधिकरण की चूक से पूर्वाग्रहपूर्ण रूप से प्रभावित हुआ है, भले ही उसका विषय-वस्तु में कोई स्वामित्व या यहां तक कि प्रत्ययी हित न हो। इसके अलावा, असाधारण मामलों में एक अजनबी या एक व्यक्ति जो प्राधिकरण के समक्ष कार्यवाही में पक्षकार नहीं था, लेकिन कार्यवाही के विषय-वस्तु में पर्याप्त और वास्तविक रुचि रखता है, भी इस नियम के दायरे में आएगा।

48. महाराष्ट्र बार काउंसिल बनाम एम. वी. दाभोलकर और अन्य 1976 एस. सी. आर. 307 में अधिस्थति के नियम में ढील दी गई थी। न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

> "परंपरागत रूप से विरोधी प्रणाली के लिए उपयोग किया जाता है, हम अलग-अलग पीड़ित व्यक्तियों की खोज करते हैं। लेकिन मुकदमेबाजी जनहित याचिका का एक नया वर्ग जहां एक वर्ग या पूरा समुदाय शामिल है (जैसे उपभोक्ता संगठन या एनएएसीपी-नेशनल एसोसिएशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल-इन अमेरिका), हमारे जैसे विकासशील देश में उभरता है, सार्वजनिक उन्मुख मुकदमेबाजी का यह पैटर्न कानून के शासन को बेहतर ढंग से पूरा करता है यदि इसे जीवन के शासन के करीब चलाना है।
>
> XXX XXX
>
> "यह संभावित आशंका कि सार्वजनिक अर्थ के साथ कानूनी अधिस्थति को व्यापक बनाने से मुकदमों की बाढ़ आ सकती

है जो न्यायाधीशों को अभिभूत कर सकती है, गलत है क्योंकि सार्वजनिक शरारत को दबाने के लिए सार्वजनिक रूप से न्यायालय का सहारा लेना न्याय प्रणाली के लिए एक सम्मान है।"

49. इस मामले में न्यायालय ने कहा कि "प्रक्रियात्मक निर्देश दासियां हैं, न्याय की स्वामिनी नहीं और निष्पक्ष खेल की विफलता वह भावना है जिसमें न्यायालयों को जुलूस के विचलन को देखना चाहिए"।

50. मुंबई कामगार सभा, बॉम्बे बनाम अब्दुलभाई फैजुल्लाभाई और अन्य ए. आई. आर. 1976 एस. सी. 1455 में, इस न्यायालय ने अधिस्थिति (लोकस स्टैंडी) के पारंपरिक नियम में ढील देकर जनता के लिए न्यायिक पहुंच में सुधार के लिए सचेत प्रयास किए।

51. सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन और अन्य ए. आई. आर. 1978 एस. सी. 1675 में, न्यायालय सामुदायिक मुकदमेबाजी को अधिकृत करते हुए पारंपरिक अधिस्थिति के नियम से अलग हो गया। न्यायालय ने एक कैदी, एक उदासीन पक्ष की एक रिट याचिका पर विचार किया, जिसमें एक साथी कैदी की यातना पर आपत्ति जताई गई थी। न्यायालय ने इस तर्क के पश्चात रिट पर विचार किया कि "इन 'शहीद' मुकदमों में व्यक्तिगत वादकारी से परे एक लाभकारी शक्ति होती है और व्यापक प्रतिनिधि आधार पर उनका विचार कानून के शासन को मजबूत करता है।" महत्वपूर्ण रूप से," लोकतंत्र में जहां जनता कई मायनों में कमजोर है, वहां अधिस्थिति की व्यापक-आधारित अवधारणा के साथ हमारी न्याय प्रणाली में लोगों की अप्रत्यक्ष भागीदारी का हवाला देते हुए न्यायालय ने एक मानवाधिकार संगठन को पीड़ित की ओर से मामले में हस्तक्षेप करने की अनुमति दी।

52. हुसैनारा खातून एंड अदर्स बनाम गृह सचिव, बिहार राज्य, पटना ए. आई. आर. 1979 एस. सी. 1369 में, पी. एन. भगवती, जे. ने कहा है कि "आज,

दुर्भाग्य से, हमारे देश में गरीबों को न्यायिक प्रणाली से बाहर कर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप वे अपनी जीवन स्थितियों में बदलाव और उन्हें न्याय दिलाने में हमारी कानूनी प्रणाली की क्षमता में विश्वास खो रहे हैं । कानूनी प्रणाली के संपर्क में आने वाले गरीब हमेशा गलत दिशा के पक्ष में रहे हैं। उन्हें हमेशा 'गरीबों का कानून' के बजाय 'गरीबों के लिए कानून' मिला है। उनके द्वारा इस कानून को कुछ रहस्यमय और निषेधात्मक माना जाता है - हमेशा उनसे कुछ न कुछ छीनना और सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को बदलने और उन्हें अधिकार और लाभ प्रदान करके उनकी जीवन स्थितियों में सुधार करने के लिए एक सकारात्मक और रचनात्मक सामाजिक उपकरण के रूप में नहीं। परिणाम यह है कि कानूनी प्रणाली ने समुदाय के कमजोर वर्ग के लिए अपनी विश्वसनीयता खो दी है।

53. प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन एआईआर 1980 एस. सी. 1535 में, एक कैदी ने एक न्यायाधीश को एक तार भेजा जिसमें उस पर जबरन हथकड़ी लगाने की शिकायत की गई और अपमान और यातना के विरुद्ध अंतर्निहित सुरक्षा की मांग की गई। न्यायालय ने अधिस्थिति के सख्त नियम में ढील देते हुए आवश्यक निर्देश दिए।

54. नगर परिषद में, रतलाम बनाम वर्धीचंद और अन्य 1980 ए. आई. आर. एस. सी. 1622 में, कृष्ण अय्यर, जे. ने लोकस स्टैंडी के नियम में ढील दीः

> "सच्चाई यह है कि हमारी कानूनी प्रणाली के लिए महान रणनीतिक महत्व के प्रक्रियात्मक न्यायशास्त्र के कुछ गहन मुद्दे हमारे सामने हैं और हमें उन पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि जो ब्रिटिश भारतीय काल के 'अधिस्थिति' के पलक झपकाने वाले नियमों से परे लोगों के लिए न्याय तक पहुंच की समस्याएं शामिल हैं। यदि न्याय के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र, जैसा कि संविधान की प्रस्तावना में कहा गया

है, अधिस्थिति के पारंपरिक व्यक्तिवाद से जनहित याचिका के सामुदायिक अभिविन्यास में बदलना है, तो इन मुद्दों पर विचार किया जाना चाहिए।

XXX XXX XXX

XXX XXX XXX

आम लोगों को जनहित की कार्रवाई के लिए क्यों प्रेरित किया जाए? जहां निर्देशात्मक सिद्धांतों में क्या करें और क्या न करें में वैधानिक अभिव्यक्ति पाई गई है, न्यायालय चुप नहीं बैठेगी और नगरपालिका सरकार को वैधानिक उपहास बनने की अनुमति नहीं देगी। कानून को अथक रूप से लागू किया जाएगा और खराब वित्त की याचिका खराब बहाना होगी जब दुख में लोग न्याय के लिए चिल्लाते हैं ....।"

55. उर्वरक निगम कामगर यूनियन (ऊपर) में जे. कृष्णा अय्यर, जे. और भगवती, जे. को सकारात्मक जवाब देना था कि क्या सरकार के स्वामित्व वाले कारखाने में श्रमिकों को कारखाने की बिक्री की वैधता पर प्रश्न उठाने का अधिकार है। उन्होंने एक उद्धरण के साथ समापन कियाः 'हेनरी पीटर ब्रूमः नीमैन रिपोर्ट अप्रैल 1956 निम्नानुसार हैः

"यह ऑगस्टस का घमंड था कि उसने रोम को ईंटों का पाया और उसे संगमरमर का बना दिया। लेकिन शासक का घमंड कितना अधिक होगा जब वह यह कहने के लिए कहेगा कि उसने कानून को प्रिय पाया और इसे सस्ते में छोड़ दिया; इसे एक सीलबंद किताब मिली और इसे एक जीवित पत्र छोड़ दिया; इसे अमीरों की विरासत पाया और इसे गरीबों की विरासत छोड़ दिया; इसे शिल्प और उत्पीड़न की दो धार वाली तलवार पाया और इसे ईमानदारी की लाठी और निर्दोषता की ढाल छोड़ दिया"।

56. पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स एंड अदर्स (ऊपर) में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी कीः

> "वह जनहित याचिका जो कानूनी सहायता आंदोलन की एक रणनीतिक शाखा है और जिसका उद्देश्य गरीब जनता की पहुंच के भीतर न्याय लाना है, जो मानवता के कम दृश्यता वाले क्षेत्र का गठन करते हैं, सामान्य पारंपरिक मुकदमेबाजी से बिल्कुल अलग तरह की मुकदमेबाजी है जो अनिवार्य रूप से एक प्रतिकूल प्रकृति की होती है, जहां दो वादी पक्षों के बीच विवाद होता है, एक दावा करता है या दूसरे के विरुद्ध राहत मांगता है और दूसरा इस तरह के दावे का विरोध करता है या ऐसी राहत का विरोध करता है। जनहित याचिका न्यायालय के समक्ष एक व्यक्ति के विरुद्ध दूसरे के अधिकार को लागू करने के उद्देश्य से नहीं लाई जाती है जैसा कि सामान्य मुकदमेबाजी के मामले में होता है, बल्कि इसका उद्देश्य सार्वजनिक हित को बढ़ावा देना और सही साबित करना है जो मांग करता है कि बड़ी संख्या में गरीब, अज्ञानी या सामाजिक या आर्थिक रूप से वंचित लोगों के संवैधानिक या कानूनी अधिकारों के उल्लंघन पर किसी को अदृष्ट और समाधान हीन नहीं छोड़ना चाहिए। यह कानून के शासन के लिए विनाशकारी होगा जो सरकार के किसी भी लोकतांत्रिक रूप में सार्वजनिक हित के आवश्यक तत्वों में से एक है। कानून के शासन से मतलब यह नहीं है कि कानून की सुरक्षा मात्र कुछ भाग्यशाली लोगों के लिए उपलब्ध होनी चाहिए या निहित स्वार्थों द्वारा अपने नागरिक और राजनीतिक अधिकार को लागू करने की आड़ में यथास्थिति की रक्षा और बनाए रखने के लिए कानून का दुरुपयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए। गरीबों के पास भी नागरिक और राजनीतिक अधिकार हैं और कानून का शासन उनके लिए भी है, हालांकि आज यह केवल कागजों पर

मौजूद है, वास्तविकता में नहीं। अगर चीनी के सौदागरों और शराब के राजाओं को अपना व्यवसाय जारी रखने और उपभोग करने वाली जनता का शोषण करके अपनी जेबें भरने का मौलिक अधिकार है, तो क्या समाज के सबसे निचले वर्ग के 'चमारों' को अपने पसीने और परिश्रम द्वारा ईमानदार जीवन जीने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है? पहले वाले प्रतिष्ठित वकीलों की एक दुर्जेय सेना के साथ न्यायालयों का रुख कर सकते हैं जिन्हें प्रति दिन चार या पांच अंकों में भुगतान किया जाता है और यदि उनके शोषण के अधिकार को मौलिक अधिकार के लेबल के तहत सरकार के विरुद्ध बरकरार रखा जाता है, तो न्यायालयों को उनके निर्भीकता और साहस के लिए प्रशंसा की जाती है और उनकी स्वतंत्रता और निर्भीकता की सराहना की जाती है। लेकिन, यदि अन्याय के शिकार गरीब और असहाय पीड़ितों के मौलिक अधिकार को जनहित याचिका द्वारा लागू करने की कोशिश की जाती है, तो मानवाधिकारों के तथाकथित चैंपियन इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के समय की बर्बादी के रूप में देखते हैं, जो उनके अनुसार, ऐसे छोटे और तुच्छ मामलों में खुद को संलग्न नहीं करना चाहिए। इसके अलावा, ये स्वयंभू मानवाधिकार कार्यकर्ता यह भूल जाते हैं कि नागरिक और राजनीतिक अधिकार, जो स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए अमूल्य हैं, हमारे लोगों की विशाल जनता के लिए मौजूद नहीं हैं। बड़ी संख्या में पुरुष, महिलाएँ और बच्चे जो हमारी आबादी का बड़ा हिस्सा हैं, आज घोर गरीबी की स्थिति में एक अमानवीय अस्तित्व जी रहे हैं : घोर गरीबी ने उनकी कमर तोड़ दी है और उनके नैतिक ताने-बाने को नष्ट कर दिया है। उन्हें मौजूदा सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में कोई विश्वास नहीं है। मानवता के ये गरीब और वंचित वर्ग कौन से नागरिक और राजनीतिक अधिकारों को लागू करने जा रहे हैं?

57. इस न्यायालय के न्यायमूर्ति भगवती ने एस. पी. गुप्ता बनाम भारत के राष्ट्रपति और अन्य ए. आई. आर. 1982 एस. सी. 149 में अपने फैसले में अधिस्थिति के पारंपरिक नियम को पूरी तरह से खारिज कर दिया, और इसे एक उदारीकृत आधुनिक शासन के साथ प्रतिस्थापित किया गया। इस मामले में, न्यायालय ने आपातकाल के दौरान न्यायाधीशों के स्थानांतरण को चुनौती देने वाले अधिवक्ताओं को अधिस्थिति प्रदान की। पारंपरिक शासन को "एक ऐसे युग का" "प्राचीन काल" "बताते हुए जब निजी कानून कानूनी परिदृश्य पर हावी था और सार्वजनिक कानून का जन्म नहीं हुआ था", न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि अधिस्थिति होने का पारंपरिक नियम अप्रचलित था। इसके स्थान पर, न्यायालय ने अधिस्थिति पर आधुनिक नियम निर्धारित कियाः

> "जहां किसी व्यक्ति या निर्धारित वर्ग के व्यक्तियों को किसी भी संवैधानिक या कानूनी अधिकार के उल्लंघन के कारण कानूनी गलती या कानूनी चोट पहुंचती है या किसी भी संवैधानिक या कानूनी प्रावधान के उल्लंघन में या कानून के अधिकार के बिना कोई बोझ लगाया जाता है या ऐसी कोई कानूनी गलत या कानूनी चोट या अवैध बोझ को खतरा होता है और ऐसा व्यक्ति या निर्धारित वर्ग के व्यक्ति गरीबी, असहायता या विकलांगता या सामाजिक या आर्थिक रूप से वंचित स्थिति के कारण राहत के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में असमर्थ होते हैं, तो जनता का कोई भी सदस्य अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में उचित निर्देश, आदेश या रिट के लिए और अनुच्छेद 32 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में, इस न्यायालय में आवेदन कर सकता है ।

58. यह पता लगाना कि अभ्यास करने वाले अधिवक्ता महत्वपूर्ण हैं एक निडर और स्वतंत्र न्यायपालिका के रखरखाव में अत्यधिक रुचि रखते हैं", न्यायालय ने आपातकाल के दौरान न्यायाधीशों के स्थानांतरण

को चुनौती देने वाले मामलों को लाने के लिए अधिवक्ताओं को आधुनिक नियम के तहत अधिस्थिति की अनुमति दी। इस मामले में, इस न्यायालय ने आगे कहा:

> ".....इसे अब एक सुस्थापित कानून माना जाना चाहिए, जहां कोई व्यक्ति जिसे कानूनी गलती या कानूनी चोट लगी है या जिसका कानूनी अधिकार या कानूनी रूप से संरक्षित हित का उल्लंघन किया गया है, वह किसी अक्षमता के कारण न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में असमर्थ है या उसके लिए कुछ अन्य पर्याप्त कारणों से न्यायालय का रुख करना व्यावहारिक नहीं है, जैसे कि उसकी सामाजिक या आर्थिक रूप से वंचित स्थिति, कोई अन्य व्यक्ति अन्यायग्रस्त या घायल व्यक्ति को न्यायिक निवारण प्रदान करने के उद्देश्य से न्यायालय की सहायता का आह्वान कर सकता है, ताकि ऐसे व्यक्ति को हुई कानूनी गलती या चोट का निवारण से वंचित न रह सके और उसे न्याय मिल सके।
>
> XXX XXX XXX
>
> XXX XXX XXX
>
> ..... आज न्यायिक प्रक्रिया में एक विशाल क्रांति हो रही है, कानून का दायरा तेजी से बदल रहा है और गरीबों की समस्याएं सामने आ रही हैं। न्यायालय को नए तरीके अपनाने होंगे और उन लोगों को न्याय तक पहुँच प्रदान करने के उद्देश्य से नई रणनीतियाँ तैयार करनी होंगी जो अपने बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित हैं और जिनके लिए आज़ादी और स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। ऐसा करने का एकमात्र तरीका रिट याचिकाओं और यहां तक कि उन लोगों के लाभ के लिए न्यायिक निवारण की मांग करने वाले सार्वजनिक उत्साही व्यक्तियों के पत्रों पर विचार करना मात्र, जिन्होंने कानूनी गलती या कानूनी चोट झेली या जिनके संवैधानिक या कानूनी

अधिकार का उल्लंघन किया गया, लेकिन जो अपनी गरीबी या सामाजिक या आर्थिक रूप से वंचित स्थिति के कारण राहत के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में असमर्थ हैं। यही भावना है कि न्यायालय न्यायिक निवारण के लिए पत्रों पर विचार कर रहा है और उन्हें रिट याचिकाओं के रूप में मान रहा है और हमें उम्मीद और विश्वास है कि देश के उच्च न्यायालय भी इस सक्रिय, लक्ष्य-उन्मुख दृष्टिकोण को अपनाएंगे"।

59. अनिल यादव और अन्य बनाम बिहार राज्य और बचचो लाल दास, अधीक्षक, केंद्रीय जेल, भागलपुर, बिहार (1982) 2 एस. सी. सी. 195 में, बिहार राज्य के भागलपुर में विचाराधीन कैदियों को अंधा करने के संबंध में एक याचिका दायर की गई थी। आरोप के अनुसार, उनकी आँखों को सुइयों से छेदा गया था और उनमें तेजाब डाला गया था। न्यायालय ने रजिस्ट्रार और सहायक रजिस्ट्रार की एक टीम को केंद्रीय जेल, भागलपुर का दौरा करने और न्यायालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भेजा था। न्यायालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए सर्वग्राही आदेश पारित किए कि इस तरह के बर्बर और अमानवीय कृत्यों की पुनरावृत्ति न हो।

60. मुन्ना और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश और अन्य राज्य, (1982) 1 एस. सी. सी. 545 में आरोप था कि विचाराधीन किशोर कैदियों को बाल सुधार गृह के बजाय कानपुर केंद्रीय जेल में भेजा गया है और उन बच्चों से वयस्क कैदियों द्वारा यौन शोषण किया गया है। इस न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अधिनियम में उल्लिखित अपवादों को छोड़कर किसी भी मामले में बच्चे को जेल नहीं भेजा जा सकता है। न्यायालय ने आगे कहा कि एक वर्ष से कम आयु के बच्चों को मात्र बाल गृहों या अन्य सुरक्षित स्थानों में ही रखा जाना चाहिए। न्यायालय ने यह भी कहा कि "जो राष्ट्र बच्चों के के बारे में चिंतित नहीं है, वह उज्ज्वल भविष्य की आशा नहीं कर सकता है।"

61. इसके बाद, कई मामलों में, न्यायालय ने पोस्ट कार्ड और पत्रों को रिट याचिकाओं के रूप में माना और निर्देश और आदेश दिए।

62. शीला बारसे बनाम महाराष्ट्र राज्य ए. आई. आर. 1983 एस. सी. 378 में, एक पत्रकार शीला बारसे ने बॉम्बे में महिला कैदियों के साथ हिरासत में हिंसा की शिकायत की। उनके पत्र को एक रिट याचिका के रूप में माना गया और न्यायालय द्वारा निर्देश दिए गए।

63. डॉ. उपेंद्र बख्शी (I) बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य 1983 (2) एस. सी. सी. 308 में दिल्ली विश्वविद्यालय के दो प्रतिष्ठित विधि प्रोफेसरों ने इस न्यायालय को एक पत्र संबोधित किया जिसमें आगरा महिला संरक्षण गृह में प्रचलित अमानवीय स्थितियों के बारे में बताया गया था। न्यायालय ने कई दिनों तक याचिका पर सुनवाई की और कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए जिनके द्वारा आगरा महिला सुरक्षा गृह में कैदियों की रहने की स्थिति में काफी सुधार किया गया।

64. वीणा सेठी (श्रीमती) बनाम बिहार राज्य और अन्य 1983 ए. आई. आर. एस. सी. 339 में कुछ कैदियों को 37 साल से लेकर 19 साल तक की अवधि के लिए जेल में रखा गया था। उन्हें कुछ अपराधों के संबंध में गिरफ्तार किया गया था और उनके विचारण के समय उन्हें पागल घोषित कर दिया गया था और अर्ध-वार्षिक चिकित्सा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ केंद्रीय जेल में रखा गया था। कुछ को दोषी ठहराया गया था, कुछ को बरी कर दिया गया था और उनमें से कुछ के विरुद्ध मुकदमे लंबित थे। उन्हें स्वस्थ घोषित किए जाने के पश्चात अधिकारियों द्वारा उनकी रिहाई के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस न्यायालय ने फैसला सुनाया कि कैदी बिना किसी गलती के और अधिकारियों के संवेदनहीन और सुस्त रवैये के कारण जेल में रहे। यदि वे दोषी साबित भी हो जाते हैं तो भी उनकी अवधि अधिकतम कारावास से अधिक होगी जो उन्हें दी जा सकती थी।

65. सलाल पनबिजली परियोजना बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य और अन्य ए. आई. आर. 1984 एस. सी. 177 में, निर्माण श्रमिकों की स्थिति के संबंध में इंडियन एक्सप्रेस में एक समाचार के आधार पर, इस न्यायालय ने ध्यान दिया और कहा कि निर्माण कार्य एक खतरनाक रोजगार है और इसलिए अनुच्छेद 24 में अधिनियमित निषेध के कारण 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को निर्माण कार्य में नियोजित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और इस संवैधानिक निषेध को केंद्र सरकार द्वारा लागू किया जाना चाहिए।

66. श्री सच्चिदानंद पांडे और एक अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य (1987) एस. सी. सी. 295 में, उनके फैसले से सहमति जताते हुए, न्यायमूर्ति खालिद ने कहा कि जनहित याचिका को तब प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए जब न्यायालयों को किसी समूह या वर्ग कार्रवाई द्वारा मौलिक अधिकारों के घोर उल्लंघन के बारे में सूचित किया जाता है या जब बुनियादी मानवाधिकारों पर हमला किया जाता है या जब ऐसे कृत्यों की शिकायतें होती हैं जो न्यायिक विवेक को झकझोर देती हैं कि न्यायालयों, विशेष रूप से इस न्यायालय को प्रक्रियात्मक बंधनों को दरकिनार करना चाहिए और ऐसी याचिकाओं की सुनवाई करनी चाहिए और जरूरतमंद, दलित और उपेक्षित लोगों की कठिनाइयों और दुखों को दूर करने के लिए सभी उपलब्ध प्रावधानों के तहत अपने क्षेत्राधिकार का विस्तार करना चाहिए।

67. बी. आर. कपूर और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य ए. आई. आर. 1990 एस. सी. 752 का मामला शाहदरा, दिल्ली में स्थित मानसिक रोगों के लिए अस्पताल के कुप्रबंधन के संबंध में जनहित याचिका से संबंधित है। इस न्यायालय ने विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की जिसने पानी की उपलब्धता, मौजूदा स्वच्छता की स्थिति, भोजन, रसोई, चिकित्सा और नर्सिंग देखभाल, रोगियों के साथ दुर्व्यवहार, कैदियों द्वारा आत्महत्या करने के प्रयास, अस्पताल में रोगियों की मृत्यु, डॉक्टरों और नर्सों की उपलब्धता आदि की समस्याओं पर प्रकाश डाला। न्यायालय ने भारत संघ से अस्पताल

को अपने हाथ में लेने और इसे बैंगलोर में निमहान्स की तर्ज पर बनाने की सिफारिश की।

68. श्रीमती नीलाबती बेहरा उर्फ ललिता बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य ए. आई. आर. 1993 एस. सी. 1960 में, इस न्यायालय ने निर्देश दिए कि राज्य और उसकी एजेंसियों द्वारा मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के उल्लंघन के लिए, 226 के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका में मौद्रिक मुआवजे का दावा न्यायसंगत है। एक सहमतिपूर्ण निर्णय में, आनंद, जे. (जैसा कि वह तब थे) ने निम्नानुसार कहा:

> "मात्र पीड़ितों को नागरिक कानून में उपलब्ध उपचारों से वंचित करने का पुराना सिद्धांत नागरिकों के अक्षम्य अधिकारों के उत्तरदायी और गारंटर के रूप में न्यायालयों की भूमिका को बहुत सीमित करता है। न्यायालयों का दायित्व है कि वे नागरिकों की सामाजिक आकांक्षाओं को पूरा करें क्योंकि अदालतें और कानून लोगों के लिए हैं और उनसे उनकी आकांक्षाओं का जवाब देने की अपेक्षा की जाती है।

69. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन, चंडीगढ़ में अपने सचिव बनाम पंजाब राज्य और अन्य (1994) 1 एससीसी 616 के माध्यम से, आरोप था कि एक अधिवक्ता, उसकी पत्नी और लगभग दो साल की उम्र के एक बच्चे का अपहरण कर उनकी हत्या कर दी गई थी। इस न्यायालय ने सी. बी. आई. के निदेशक को जांच करने और न्यायालय को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया।

70. नवकिरण सिंह और अन्य बनाम मुख्य सचिव और अन्य के माध्यम से पंजाब राज्य (1995) 4 एससीसी 591 में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं ने एक पत्र याचिका में पंजाब राज्य में अधिवक्ताओं के अपहरण/उन्मूलन के बारे में चिंता व्यक्त की। इस न्यायालय ने सी. बी. आई. को मामले की जांच करने का निर्देश दिया और पंजाब राज्य

को उन अधिवक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने का भी निर्देश दिया, जिन्हें वास्तव में आतंकवादियों/असामाजिक तत्वों से अपनी जान को खतरा है। न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि जिला न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार द्वारा सुरक्षा के लिए अनुरोध की सिफारिश की जाती है, तो इसे वास्तविक माना जा सकता है और राज्य सरकार सहानुभूतिपूर्वक इस पर विचार कर सकती है।

71. दिल्ली घरेलू कामकाजी महिला फोरम बनाम भारत संघ और अन्य (1995-995) 1 एस. सी. सी. 14 में, न्यायालय ने महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के बारे में गम्भीर चिंता व्यक्त की। न्यायालय ने महत्वपूर्ण निर्देश दिए और कहा कि पीड़ितों के लिए मुआवजा न्यायालय द्वारा अपराधी को दोषी ठहराए जाने पर और आपराधिक चोट मुआवजा बोर्ड द्वारा दिया जाएगा या चाहे दोषसिद्धि हुई हो या नहीं। बोर्ड दर्द, पीड़ा और सदमे के साथ-साथ गर्भावस्था के कारण कमाई के नुकसान और बलात्कार के परिणामस्वरूप हुए बच्चे के जन्म के खर्च को ध्यान में रखेगा।

72. सिटिजन्स फॉर डेमोक्रेसी बनाम असम राज्य और अन्य (1995) 3 एस. सी. सी. 743 में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि हथकड़ी लगाना और रस्सियों से बांधना अमानवीय है और अंतर्राष्ट्रीय कानून और देश के कानून के तहत गारंटीकृत मानवाधिकारों का पूर्ण उल्लंघन है। न्यायालय ने पैरा 15 में निम्नलिखित टिप्पणी कीः

> "15. अस्पताल में बंद मरीज़ों-कैदियों को हथकड़ी लगाना और उन्हें रस्सियों से बांधना, कम से कम हम कह सकते हैं, अमानवीय है और अंतर्राष्ट्रीय कानून और देश के कानून के तहत किसी व्यक्ति को दिए गए मानवाधिकारों का सरासर उल्लंघन है। इसलिए, हमारा विचार है कि प्रतिवादी की कार्रवाई पूरी तरह से अनुचित और कानून के विरुद्ध

थी। हम निर्देश देते हैं कि यदि बंदी अभी भी अस्पताल में हैं तो उन्हें तत्काल प्रभाव से जंजीरों और रस्सियों से मुक्त किया जाए।

73. परमजीत कौर (श्रीमती) बनाम पंजाब राज्य और अन्य (1996) 7 एस. सी. सी. 20 में, इस न्यायालय के एक न्यायाधीश को एक टेलीग्राम भेजा गया था जिसे बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के रूप में माना गया था। आरोप था कि अपीलकर्ता के पति का अमृतसर के व्यस्त आवासीय क्षेत्र से पुलिस की वर्दी में कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया था। न्यायालय ने इसे गम्भीरता से लिया और केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मामले की जांच कराने का निर्देश दिया।

74. एम. सी. मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य (1996) 6 एस. सी. सी. 756 में, न्यायालय बाल श्रम के मामलों पर विचार कर रहा था और न्यायालय ने पाया कि बाल श्रम अत्यधिक गरीबी, लाभकारी रोजगार के अवसर की कमी और आय रुक-रुक कर होना और निम्न जीवन स्तर से उत्पन्न होता है। न्यायालय ने कहा कि संगठित क्षेत्र में बाल श्रम की पहचान करना संभव है, जो कुल बाल श्रम का एक छोटा हिस्सा है, यह समस्या मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र से संबंधित है जहां अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

75. डी. के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997) 1 एस. सी. सी. 416 में, इस न्यायालय ने कहा कि हिरासत में मौत शायद कानून के शासन द्वारा शासित सभ्य समाज में सबसे खराब अपराधों में से एक है। संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 (1) में निहित अधिकारों को ईर्ष्यापूर्वक और ईमानदारी से संरक्षित करने की आवश्यकता है। अनुच्छेद 21 में "जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता" अभिव्यक्ति में मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार शामिल है और इस प्रकार इसमें राज्य या उसके कार्यकर्ताओं द्वारा यातना और हमले के विरुद्ध गारंटी भी शामिल होगी। अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत बहुमूल्य अधिकार से दोषियों, विचाराधीन कैदियों, बंदियों और हिरासत में अन्य

कैदियों को वंचित नहीं किया जा सकता है, सिवाय कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के, जिसमें कानून द्वारा अनुमत उचित प्रतिबंध लगाए जाते हैं। न्यायालय ने बहुत महत्वपूर्ण निर्देश दिए जिनका पालन करना सभी संबंधितों के लिए अनिवार्य है।

76. विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य (1997) 6 एस. सी. सी. 241 में, इस न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत कामकाजी महिलाओं के मूल अधिकार के प्रवर्तन के संबंध में निर्देश दिए। न्यायालय ने सर्वग्राही दिशानिर्देश और मानदंड दिए और महिलाओं के इन अधिकारों की सुरक्षा और उनके कार्यस्थलों पर उन्हें लागू करने का निर्देश दिया।

77. हाल ही में तय किए गए मामले प्रजवाला बनाम भारत संघ और अन्य (2009) 4 एस. सी. सी. 798 में, इस न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें यह महसूस किया गया था कि विकलांग व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के प्रारंभ होने के बावजूद, विकलांग लोगों को वरीयता नहीं दी जाती है। न्यायालय ने राज्य सरकारों/स्थानीय अधिकारियों को अधिनियम की धारा 43 में आरोपित विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटित करने का निर्देश दिया और धारा 43 में इंगित विभिन्न मदों के अनुसार विकलांग लोगों को वरीयता दी जाए और भूमि रियायती दरों पर दी जाए। आरक्षण का प्रतिशत राज्य सरकारों के विवेकाधिकार पर छोड़ा जा सकता है। यद्यपि प्रतिशत तय करते समय विकलांग व्यक्तियों के कुल प्रतिशत को ध्यान में रखा जाएगा।

78. अविनाश मेहरोत्रा बनाम भारत संघ और अन्य (2009) 6 एस. सी. सी. 398 में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जब तमिलनाडु के एक निजी स्कूल में आग लगने से 93 बच्चों को जिंदा जला दिया गया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि स्कूल में न्यूनतम सुरक्षा मानक उपाय नहीं थे। न्यायालय ने

ऐसे सभी स्कूलों में भविष्य की त्रासदियों की रक्षा के लिए निर्देश दिए कि सुरक्षा और बचाव के डर से स्वतंत्र शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है, इसलिए सरकार को नेशनल बिल्डिंग कोड लागू करनी चाहिए और बच्चों के लिए स्कूलों के निर्माण में उक्त आदेशों का पालन करना चाहिए।

79. इन सभी उपर्युक्त मामलों से पता चलता है कि न्यायालयों ने नागरिकों के मूल अधिकार की रक्षा और संरक्षण के आदेश, लोकस स्टैंडी के नियम में ढील देते हुए, संबंधित अधिकारियों को कई निर्देश दिए।

80. हम इन मामलों को गुणा करके फैसले पर अधिक बोझ नहीं डालना चाहेंगे, लेकिन इन मामलों के संक्षिप्त विवरण से पता चलता है कि समाज के हाशिए पर पड़े, वंचित और गरीब वर्गों के मौलिक अधिकारों को संरक्षित करने और उनकी रक्षा करने के लिए न्यायालयों ने अधिस्थिति के पारंपरिक नियम में ढील दी और पीड़ित व्यक्तियों की परिभाषा को व्यापक बनाया और दिशा-निर्देश दिए। हम इस अवधि के मामलों को जनहित याचिका के पहले चरण के रूप में बताना चाहेंगे जहां न्यायालय ने अधिस्थिति के नियम में ढील दी थी। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने समाज के गरीब और हाशिए पर पड़े लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा और संरक्षण के लिए अपने अभिनव प्रयासों के कारण जनता की नज़रों में बहुत सम्मान अर्जित किया और बहुत विश्वसनीयता प्राप्त की।

<u>चरण-II - पारिस्थितिकी और पर्यावरण के संरक्षण और सुरक्षा के लिए दिशा-निर्देश</u>

81. जनहित याचिका का दूसरा चरण 1980 के दशक में शुरू हुआ और यह न्यायालयों के नवीनीकरण और रचनात्मकता से संबंधित था, जहां पारिस्थितिकी और पर्यावरण की रक्षा के लिए निर्देश दिए गए थे।

82. ऐसे कई मामले हैं जहां वन क्षेत्र, पारिस्थितिकी और पर्यावरण की सुरक्षा करने का प्रयास किया और उस संबंध में आदेश पारित किए गए हैं। वास्तव में, सर्वोच्च न्यायालय की एक नियमित वन पीठ (हरित पीठ) है और नियमित रूप से विभिन्न वन क्षेत्र, अवैध खनन, समुद्री जीवन और वन्यजीवों के विनाश आदि के संबंध में आदेश और निर्देश पारित करती है। कुछ मामलों का संदर्भ केवल उदाहरण के लिए दिया गया है।

83. दूसरे चरण में, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय ने इस संबंध में कई आदेश और निर्देश पारित किए।

84. हाल का उदाहरण दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर दिल्ली के महानगर शहर में सभी सार्वजनिक परिवहन का डीजल इंजन से सीएनजी इंजन में रूपांतरण करना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रदूषण के स्तर में कमी आई है और यह पिछले कई वर्षों से पूरी तरह से देखा जा रहा है। सार्वजनिक परिवहन के लिए दिल्ली की सड़कों पर मात्र सीएनजी वाहनों को चलने की अनुमति है।

85. लुईस एर्ड्रिच बिगोग्रेस, एक पर्यावरणविद् ने ठीक ही कहा है कि "घास और आकाश दो कैनवस हैं जिनमें पृथ्वी के समृद्ध विवरण खींचे जाते हैं। 1980 के दशक में, इस न्यायालय ने वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, पर्यावरणीय क्षरण की समस्या पर विशेष ध्यान दिया और यह सुनिश्चित करने के लिए कई निर्देश और आदेश पारित किए कि पर्यावरण पारिस्थितिकी, वन्यजीवों को बचाया जाना, परिरक्षित और सरंक्षित किया जाना चाहिए। न्यायालय के अनुसार, भारत की धरती पर हो रहे अन्याय का पैमाना विनाशकारी है। हर दिन सैकड़ों हजारों कारखाने प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों के बिना काम कर रहे हैं। हजारों भारतीय खदानों में जाते हैं और बिना उचित सुरक्षा के खतरनाक काम करते हैं। हर दिन लाखों लीटर अनुपचारित कच्चे अपशिष्ट

पदार्थ हमारी नदियों में फेंके जाते हैं और लाखों टन खतरनाक अपशिष्ट आसानी से पृथ्वी पर फेंके जाते हैं। पर्यावरण इतना खराब हो गया है कि हमारा पालन-पोषण करने के बजाय यह हमें जहर दे रहा है। इस परिदृश्य में, बड़ी संख्या में मामलों में, सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया और अनगिनत निर्देश जारी किये।

86. हम इस न्यायालय द्वारा तय किए गए कुछ महत्वपूर्ण मामलों का संक्षिप्त विवरण देते हैं। दिल्ली में ओलियम गैस रिसाव से संबंधित उच्चतम न्यायालय के समक्ष लाए गए सबसे शुरुआती मामलों में से एक था। पर्यावरण और लोगों के जीवन और स्वास्थ्य को हो रहे नुकसान को रोकने के लिए, न्यायालय ने कई आदेश पारित किए। इसे एम. सी. मेहता और एक अन्य बनाम भारत संघ और अन्य ए. आई. आर. 1987 एस. सी. 1086 के रूप में जाना जाता है। इस मामले में न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि एक उद्यम जो खतरनाक या स्वाभाविक रूप से खतरनाक उद्योग में लगा हुआ है, जो कारखाने में काम करने वाले और आसपास के क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए संभावित खतरा पैदा करता है, सामुदायिक समुदाय के लिए यह सुनिश्चित करना एक आत्यन्तिक और गैर-प्रत्यायोजित कर्तव्य है कि उसने जो गतिविधि की है, उसकी खतरनाक या स्वाभाविक रूप से खतरनाक प्रकृति के कारण किसी को भी कोई नुकसान न हो। न्यायालय ने निर्देश दिया कि उद्यम को सुरक्षा के उच्चतम मानकों को अपनाना चाहिए और यदि ऐसी गतिविधि के कारण कोई नुकसान होता है, तो उद्यम को इस तरह के नुकसान की भरपाई करने के लिए आत्यन्तिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए और उद्यम को यह कहने का कोई जवाब नहीं होना चाहिए कि उसने आत्यन्तिक रूप से उचित देखभाल की थी और यह कि नुकसान उसकी ओर से किसी भी लापरवाही के बिना हुआ।

87. ग्रामीण मुकदमेबाजी और हकदारी केंद्र, देहरादून और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य ए. आई. आर. 1985 एस. सी. 652 मामले में,

उच्चतम न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान देते हुए दून घाटी में सभी चूने के पत्थर की खदानों को बंद करने का आदेश दिया कि चूने के पत्थर की खदानों और क्षेत्र में खुदाई ने पानी के झरनों और पर्यावरणीय पारिस्थितिकी को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया था। चूने के पत्थर की खदानों को बंद करने पर टिप्पणी करते हुए, न्यायालय ने कहा कि इससे निस्संदेह चूने के पत्थर की खदानों के मालिकों को कठिनाई होगी, लेकिन यह वह कीमत है जो लोगों के स्वस्थ वातावरण में रहने के अधिकार की रक्षा और सुरक्षा के लिए चुकानी होगी, जिसमें पारिस्थितिक संतुलन में न्यूनतम गड़बड़ी होगी और उन्हें और उनके मवेशियों, घरों और कृषि भूमि के लिए कोई खतरा नहीं होगा और हवा, पानी और पर्यावरण पर अनुचित प्रभाव नहीं पड़ेगा।

88. संविधान के अनुच्छेद 21 की न्यायालय की व्याख्या के कारण पर्यावरणीय जनहित याचिका सामने आई है। छेत्रीय परदूषण मुक्ति संघर्ष समिति बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य ए. आई. आर. 1990 एस. सी. 2060 मामले में, न्यायालय ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार जीवन की गुणवत्ता का आनंद लेने और जीवन जीने का मौलिक अधिकार है। कानून के उल्लंघन या अपमान में किसी के आचरण से जो कुछ भी खतरे में डालता है या बाधित करता है, लोगों के जीवन की गुणवत्ता और रहन-सहन को संविधान के अनुच्छेद 32 का सहारा लेने का हकदार है।

89. इस न्यायालय ने सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य और अन्य एआईआर 1991 एससी 420 में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत लोगों को जीवन का पूरा आनंद लेने के लिए प्रदूषण मुक्त पानी और हवा का आनंद लेने का अधिकार है। यदि कुछ भी कानूनों का अपमान करके जीवन की गुणवत्ता को खतरे में डालता है या बाधित करता है, तो एक नागरिक को जल या वायु के प्रदूषण को दूर करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 का सहारा लेने का अधिकार है जो जीवन की गुणवत्ता के लिए हानिकारक हो सकता है।

90. एम. सी. मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड अन्य (1988) 1 एस. सी. सी. 471 के मामले में चमड़ा कारखानों द्वारा कानपुर में गंगा नदी में छोड़े गए व्यापारिक अपशिष्टों के कारण होने वाले प्रदूषण से संबंधित है। न्यायालय ने विशेषज्ञों की समिति से रिपोर्ट मांगी और पर्यावरण और पारिस्थितिकी को बचाने के निर्देश दिए। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि "सामान्य कानून में नगर निगम को एक नदी तट के मालिक द्वारा लाई गई कार्रवाई में निषेधाज्ञा द्वारा रोका जा सकता है, जिसे निगम द्वारा नदी में अपर्याप्त रूप से उपचारित सीवेज का निर्वहन करके नदी में पानी के प्रदूषण के कारण नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता नदी तट का मालिक नहीं है। वह उन लोगों के जीवन की रक्षा करने में रुचि रखने वाला व्यक्ति है जो गंगा नदी में बहने वाले पानी का उपयोग करते हैं और याचिका को बनाए रखने के लिए उनके अधिकार पर विवाद नहीं किया जा सकता है। गंगा नदी के प्रदूषण के कारण होने वाला उपद्रव एक सार्वजनिक उपद्रव है, जो व्यापक रूप से व्यापक है और इसके प्रभाव में अंधाधुंध है और बड़े पैमाने पर समुदाय से अलग किसी विशेष व्यक्ति से इसे रोकने के लिए कार्यवाही करने की उम्मीद करना उचित नहीं होगा। याचिका को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार किया गया है। तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर, याचिकाकर्ता उन वैधानिक प्रावधानों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का हकदार है, जो नगरपालिका अधिकारियों और जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत गठित बोर्डों पर शुल्क लगाते हैं।"

91. वेल्लोर सिटिजन्स वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ और अन्य ए. आई. आर. 1996 एस. सी. 2715 में, इस न्यायालय ने फैसला सुनाया कि एहतियाती सिद्धान्त और प्रदूषक भुगतान सिद्धान्त देश के पर्यावरण कानून का हिस्सा हैं। इस न्यायालय ने अनुच्छेद 47, 48ए और 51ए (जी) को

पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए संवैधानिक जनादेश का हिस्सा घोषित किया।

92. एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ और अन्य ए. आई. आर. 1988 एस. सी. 1037 में, इस न्यायालय ने कहा कि किसी भी शहरी क्षेत्र से नदी में बहने वाले घरेलू मलजल की तुलना में चमड़ा उद्योग से गंगा नदी में निकलने वाला अपशिष्ट दस गुना हानिकारक है। न्यायालय ने आगे कहा कि चमड़ा कारखानों की वित्तीय क्षमता को प्राथमिक उपचार संयंत्र स्थापित करने की आवश्यकता के बिना अप्रासंगिक माना जाना चाहिए। जिस तरह एक उद्योग जो अपने श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं कर सकता है, उसी तरह एक चर्म उद्योग जो प्राथमिक उपचार संयंत्र स्थापित नहीं कर सकता है, उसे बड़े पैमाने पर जनता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए अस्तित्व में बने रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

93. एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ और अन्य ए. आई. आर. 1997 एस. सी. 734 में, इस न्यायालय ने कहा कि ताजमहल के पास उद्योगों द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन से प्राचीन स्मारक ताजमहल को संरक्षण और सुरक्षा करने के लिए, न्यायालय ने 299 उद्योगों को कोक/कोयले के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। न्यायालय ने आगे उन्हें संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सी. एन. जी.) में स्थानांतरित करने या उन्हें फिर से स्थापित करने का निर्देश दिया।

94. ए. पी. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम प्रो. एम. वी. नायडु (सेवानिवृत्त) और अन्य (1999) 2 एस. सी. सी. 718 में, इस न्यायालय ने ए. फ्रिट्श "पर्यावरण नैतिकता: संबंधित नागरिकों के लिए विकल्प" को उद्धृत किया। उसी को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

> "पारिस्थितिकी की मूल अंतर्दृष्टि यह है कि सभी जीवित चीजें परस्पर संबंधित प्रणालियों में मौजूद हैं; निर्जनता में कुछ भी मौजूद

नहीं है। वेब जैसी विश्व प्रणाली; एक कतरा को तोड़ना का अर्थ है सभी में कंपन पैदा करना; जो कुछ भी एक भाग के साथ होता है वह बाकी सभी के लिए प्रभाव डालता है। हमारे कार्य व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक होते हैं; वे पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में गूंजते हैं। [ए. फ्रिट्श द्वारा साइंस एक्शन गठबंधन, पर्यावरण नैतिकताएँ : संबंधित नागरिकों के लिए विकल्प 3-4 (1980)]: (1988) खंड 12 हार्व. पर्यावरण. एल. ईव. 313 पर)। "

95. इस मामले में न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि न्यायालय के निर्देशों को जनहित, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण उन्मूलन और सतत विकास की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। सतत विकास सुनिश्चित करते समय, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि पर्यावरण या पारिस्थितिकी के लिए कोई खतरा न हो।

96. एस्सार ऑयल लिमिटेड बनाम हलार उत्कर्ष और अन्य ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 1834 में, आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखते हुए, न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

> “26. स्टॉकहोम घोषणा में मानवता और उसके पर्यावरण को बनाए रखने के उद्देश्यों के लिए व्यापक मापदंड और दिशा-निर्देश देते हुए कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया था। इन मापदंडों में से कुछ सिद्धांत निकाले गए हैं जो वर्तमान बहस के लिए प्रासंगिक हैं। सिद्धान्त 2 में यह प्रावधान है कि वायु, जल, भूमि सहित पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों, विशेष रूप से प्राकृतिक पारिस्थितिकी प्रणालियों के प्रतिनिधि नमूनों को सावधानीपूर्वक योजना और उचित प्रबंधन के माध्यम द्वारा वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लाभ के लिए संरक्षित किया जाना चाहिए। इसी तरह, चौथा सिद्धान्त कहता है कि "मनुष्य की वन्यजीवों की विरासत और उनके निवास स्थान की रक्षा

और बुद्धिमानी से प्रबंधन करने की विशेष उत्तरदायित्व है जो अब प्रतिकूल कारकों के संयोजन से गंभीर रूप से खतरे में हैं। इसलिए, आर्थिक विकास की योजना बनाने में वन्यजीवों सहित प्रकृति संरक्षण को महत्व दिया जाना चाहिए। ये दोनों सिद्धांत आर्थिक विकास प्रदान करते समय पर्यावरण के विचारों को ध्यान में रखने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं। आर्थिक विकास की आवश्यकता पर सिद्धान्त 8 में चर्चा की गई है जहाँ यह कहा गया है कि "आर्थिक और सामाजिक विकास मनुष्य के लिए एक अनुकूल जीवन और कार्य वातावरण सुनिश्चित करने और पृथ्वी पर ऐसी परिस्थितियाँ बनाने के लिए आवश्यक है जो जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए आवश्यक हैं।"

97. सतत विकास पर, कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड बनाम श्री सी. केंचप्पा और अन्य एआईआर 2006 एससी 2038 में, हम में से एक (भंडारी, जे.) ने कहा कि सतत विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन होना चाहिए। इस न्यायालय ने कहा कि विकास के लिए भूमि के अधिग्रहण से पहले, पर्यावरण पर विकास के परिणाम और प्रतिकूल प्रभाव को ठीक से समझा जाना चाहिए और विकास के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाना चाहिए ताकि वे पारिसम्पतिकी और पर्यावरण को गंभीर रूप से प्रभावित न करें; राज्य औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड विकास के लिए भूमि आवंटित करने से पहले कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मंजूरी प्राप्त करने के लिए आवंटन की शर्त को शामिल करेगा। भूमि के आवंटन की उक्त निर्देशिका शर्त को भविष्य में स्वीकृत की जाने वाली सभी परियोजनाओं के लिए एक अनिवार्य शर्त में परिवर्तित किया जाना चाहिए।

98. एम. सी. मेहता बनाम कमल नाथ और अन्य (2000) 6 एस. सी. सी. 213 के मामले में इस न्यायालय के एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में, इस न्यायालय की राय थी कि अनुच्छेद 48 ए और 51-ए (जी) पर संविधान के अनुच्छेद 21

के आलोक में विचार किया जाना चाहिए। मूल पर्यावरण तत्वों, अर्थात् हवा, पानी और मिट्टी, जो "जीवन" के लिए आवश्यक हैं, की कोई भी गड़बड़ी अनुच्छेद 21 के अर्थ के भीतर "जीवन" के लिए खतरनाक होगी। अनुच्छेद 21 के तहत अधिकारों को लागू करने के मामले में, इस न्यायालय ने उपरोक्त निर्दिष्ट अधिनियमों के प्रावधानों को लागू करने के अलावा, अनुच्छेद 14 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों को भी प्रभावी किया है और यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि पर्यावरण को बाधित करके उन अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है, तो वह न मात्र पारिस्थितिक संतुलन की बहाली के लिए, बल्कि उन पीड़ितों के लिए भी हर्जाना दे सकता है जो उस गड़बड़ी के कारण पीड़ित हुए हैं। "जीवन" की रक्षा के लिए, "पर्यावरण" की रक्षा के लिए और "वायु, जल और मिट्टी" को प्रदूषण से बचाने के लिए, इस न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों के माध्यम द्वारा नागरिकों और व्यक्तियों को अनुच्छेद 21, के तहत उपलब्ध अधिकारों को समान रूप से प्रभावी बनाया है।

99. न्यायालय ने प्रदूषक-भुगतान के सिद्धान्त पर भी जोर दिया। न्यायालय के अनुसार, प्रदूषण एक नागरिक अपराध है। यह समग्र रूप से समुदाय के विरुद्ध किया गया अत्याचार है। इसलिए, जो व्यक्ति प्रदूषण पैदा करने का दोषी है, उसे पर्यावरण और पारिस्थितिकी की बहाली के लिए नुकसान या मुआवजे का भुगतान करना पड़ेगा।

100. प्रबंध निदेशक, ए.पी.एस.आर.टी.सी. बनाम एस. पी. सत्यनारायण एआईआर 1998 एससी 2962 में, इस न्यायालय ने भारत सरकार द्वारा प्रकाशित श्वेत पत्र का उल्लेख किया कि वाहन प्रदूषण 1970 में 20 प्रतिशत की तुलना में वायु प्रदूषण में 70 प्रतिशत का योगदान है। इस न्यायालय ने इस न्यायालय द्वारा नियुक्त भूरे लाल की एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सर्वग्राही निर्देश दिए।

101. ध्वनि प्रदूषण ए. आई. आर. 2005 एस. सी. 3136 के संदर्भ में, यह न्यायालय ध्वनि प्रदूषण के मुद्दे से निपट रहा था। इस न्यायालय की राय थी कि ध्वनि प्रदूषण के खतरनाक प्रभावों के प्रति सामान्य जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। विशेष रूप से, हमारे देश में आम तौर पर लोगों को ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी नहीं होती है और वे स्वयं सहित समाज को ध्वनि प्रदूषण के उत्पादन और उत्सर्जन को रोकने से कैसे लाभान्वित करते हैं।

102. इंडियन काउंसिल फॉर एनविरो-लीगल एक्शन बनाम भारत संघ और अन्य (1996) 5 एस. सी. सी. 281 में याचिका में मुख्य शिकायत यह है कि 19.2.1991 की एक अधिसूचना में तटीय क्षेत्रों को तटीय विनियमन क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है जो उक्त क्षेत्रों में गतिविधियों को नियंत्रित करती है, उसे क्रियान्वित या लागू नहीं किया गया है। इससे उक्त तटीय क्षेत्रों में पारिस्थितिकी का निरंतर क्षरण हो रहा है। न्यायालय ने कहा कि पारिस्थितिकी की कीमत पर या व्यापक पर्यावरण विनाश और उल्लंघन करके आर्थिक विकास की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए; साथ ही, पारिस्थितिकी और पर्यावरण को संरक्षित करने की आवश्यकता को आर्थिक और अन्य विकास में बाधा नहीं डालनी चाहिए। विकास और पर्यावरण दोनों साथ-साथ चलना चाहिए, दूसरे शब्दों में, पर्यावरण की कीमत पर विकास नहीं होना चाहिए और इसके विपरीत भी, लेकिन उचित ध्यान रखते हुए और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए विकास होना चाहिए।

103. एस. जगन्नाथ बनाम भारत संघ और अन्य (1997) 2 एस. सी. सी. 87 में, इस न्यायालय ने समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए काम करने वाले एक स्वैच्छिक संगठन, ग्राम स्वराज आंदोलन द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर विचार किया, जिसमें याचिकाकर्ता ने तटीय क्षेत्र विनियमन अधिसूचना दिनांक 19.2.1991 को लागू करने और पारिस्थितिक रूप से नाजुक तटीय क्षेत्रों में झींगे की खेती के गहन और अर्ध-गहन प्रकार को

रोकने की मांग की । इस न्यायालय ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्देश दिएः

1. केंद्र सरकार एक प्राधिकरण का गठन करेगी जो उक्त प्राधिकरण को पारिस्थितिक रूप से नाजुक तटीय क्षेत्रों, समुद्र तट, तट और अन्य तटीय क्षेत्रों की रक्षा के लिए और विशेष रूप से तटीय राज्यों में झींगा संस्कृति उद्योग द्वारा उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक सभी शक्तियां प्रदान करेगी।

2. केंद्र सरकार द्वारा गठित प्राधिकरण "एहतियाती सिद्धान्त" और "प्रदूषक भुगतान" सिद्धान्तों को लागू करेगा।

3. झींगा संवर्धन उद्योग/झींगा तालाब सी. आर. जेड. अधिसूचना के पैरा 2 (i) में निहित निषेध के दायरे में आते हैं। सी. आर. जेड. अधिसूचना में परिभाषित तटीय विनियमन क्षेत्र के भीतर किसी भी झींगा संवर्धन तालाब का निर्माण या स्थापना नहीं की जा सकती है। यह सभी समुद्रों, खाड़ी, ज्वारनदमुख, खाड़ी नदियों और अप्रवाही जल पर लागू होगा। यह निर्देश पारंपरिक और उन्नत पारंपरिक प्रकार की प्रौद्योगिकियों (जैसा कि अलगारस्वामी रिपोर्ट में परिभाषित किया गया है) पर लागू नहीं होगा जो तटीय निचले क्षेत्रों में प्रचलित हैं।

4. सी. आर. जेड. अधिसूचना के तहत परिभाषित तटीय विनियमन क्षेत्र में संचालित/स्थापित सभी जलकृषि उद्योग/झींगा पालन उद्योग/झींगा पालन तालाबों को 31 मार्च, 1997 से पहले उक्त क्षेत्र से ध्वस्त कर दिया जाएगा और हटा दिया जाएगा।

5. कृषि भूमि, नमक भूमि, मैंग्रोव, आर्द्र भूमि, वन भूमि, गाँव के सामान्य उद्देश्य के लिए भूमि और सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए भूमि का उपयोग झींगा संवर्धन तालाबों के निर्माण के लिए नहीं किया जाएगा।

6. चिल्का झील और पुलिकट झील (यदुरपट्टू और नेलपट्टू जैसे पक्षी अभयारण्यों सहित) के 1000 मीटर के भीतर किसी भी जलीय कृषि उद्योग/झींगा पालन उद्योग/झींगा पालन तालाबों का निर्माण/स्थापना नहीं की जाएगी।

7. 1000 मीटर के उक्त क्षेत्र में पहले से चल रहे और चल रहे एक्वाकल्चर उद्योग/झींगा संवर्धन उद्योग/झींगा संवर्धन तालाबों को 31 मार्च, 1997 से पहले बंद कर दिया जाएगा और ध्वस्त कर दिया जाएगा।

8. न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि तटीय विनियमन क्षेत्र से 1000 मीटर के भीतर काम करने वाले झींगा उद्योग "प्रदूषक भुगतान" सिद्धान्त के आधार पर प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी होंगे।

9. प्राधिकरण को दो शीर्षों के तहत मुआवजे की गणना करने का निर्देश दिया गया था, अर्थात् पारिस्थितिकी को उलटने और व्यक्तियों को भुगतान के लिए।

10. प्रदूषकों से वसूल की गई मुआवजे की राशि को "पर्यावरण संरक्षण कोष" नामक एक अलग मद के तहत जमा किया जाएगा और इसका उपयोग प्राधिकरण द्वारा पहचाने गए प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा देने और क्षतिग्रस्त पर्यावरण को बहाल करने के लिए भी किया जाएगा।

104. न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को पर्याप्त जुर्माना भी लगाया।

105. पर्यावरण, पारिस्थितिकी, वन, समुद्री जीवन, वन्यजीव आदि के व्यापक विनाश के कारण न्यायालयों ने व्यापक जनहित में बड़ी संख्या में मामलों में निर्देश दिए। न्यायालयों ने पारिस्थितिकी, पर्यावरण, वनों, पहाड़ियों,

नदियों, समुद्री जीवन, वन्यजीवों आदि की रक्षा और संरक्षण के लिए गम्भीर प्रयास किए। इसे भारत में जनहित याचिका का दूसरा चरण कहा जा सकता है।

<u>शासन में पारदर्शिता और ईमानदारी - जनहित याचिका का चरण-III</u>

106. 1990 के दशक में, सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका के दायरे और सीमा का और अधिक विस्तार किया। उच्च न्यायालयों ने भी अनुच्छेद 226 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का अनुसरण किया और भ्रष्टाचार का पता लगाने और राज्य के शासन में ईमानदारी और नैतिकता बनाए रखने के लिए कई निर्णय, आदेश या निर्देश पारित किए। प्रशासन की एक कुशल प्रणाली और देश के विकास के लिए शासन में ईमानदारी एक अनिवार्य शर्त है और शासन में ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता भ्रष्टाचार का अभाव है। इसे मोटे तौर पर जनहित याचिका का तीसरा चरण कहा जा सकता है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने महत्वपूर्ण आदेश पारित किए हैं।

107. विनीत नारायण और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य ए. आई. आर. 1998 एस. सी. 889 का मामला अपनी तरह का एक उदाहरण है। उस मामले में, याचिकाकर्ता, जो एक पत्रकार थे, ने एक जनहित याचिका दायर की। उनके अनुसार, केंद्रीय जांच ब्यूरो और राजस्व अधिकारियों जैसी प्रमुख जांच एजेंसियां अपने कानूनी दायित्व का पालन करने और उचित कार्रवाई करने में विफल रहीं, जब उन्होंने पाया कि एक आतंकवादी के साथ जांच के दौरान, प्रभावशाली राजनेताओं और नौकरशाहों को किए गए विशाल भुगतान, जिन्हें 'जैन डायरी' कहा जाता है, के विस्तृत विवरण और इसी तरह की प्रकृति के मामले में निर्देश भी मांगे गए थे जो आगे भी हो सकते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा कई निर्देश जारी किए गए थे। उस मामले में न्यायालय ने कहा कि "यह सामान्य बात है कि सार्वजनिक पदों के धारकों को केवल

सार्वजनिक हित में प्रयोग करने की कुछ शक्ति सौंपी गई है और इसलिए, उनके द्वारा कार्यालय लोगों के विश्वास के रूप में धारण किया जाता है।"

108. एक अन्य महत्वपूर्ण मामला राजीव रंजन सिंह 'ललन' और एक अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (2006) 6 एस. सी. सी. 613 है। यह जनहित याचिका बिहार राज्य में पशुपालन विभाग में सार्वजनिक निधि के बड़े पैमाने पर अवमूल्यन और खातों में सैकड़ों करोड़ रुपये के धोखाधड़ी से संबंधित है। यह कहा गया था कि प्रतिवादी ने सरकारी अभियोजक की नियुक्ति में हस्तक्षेप किया था। इस न्यायालय ने महत्वपूर्ण निर्देश दिए।

109. एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ और अन्य (2007) 1 एस. सी. सी. 110 के एक अन्य मामले में, एक परियोजना जिसे "ताज हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना" के रूप में जाना जाता है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई थी। यमुना नदी को मोड़ने और आगरा किले और ताजमहल के बीच 75 एकड़ भूमि को पुनः प्राप्त करने और पुनः प्राप्त भूमि का उपयोग खाद्य प्लाजा, दुकानों और मनोरंजन गतिविधियों के निर्माण के लिए करने का एक मुख्य उद्देश्य था। न्यायालय ने एक विस्तृत जांच का निर्देश दिया जो केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा की गई थी। सी. बी. आई. की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने एफ़. आई. आर. दर्ज करने और मामले में आगे की जाँच करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने संबंधित पर्यावरण मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निभाई गई भूमिका पर सवाल उठाया। इस न्यायालय के हस्तक्षेप से उक्त परियोजना रुक गयी।

110. ये कुछ ऐसे मामले हैं जहाँ सरकारी अधिकारियों की प्रभावकारिता, नीति और नैतिकता को अपने वैधानिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की जांच के तहत निर्देशित किया गया था।

111. एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ और अन्य (2007) 12 स्केल 91 में, एक अन्य जनहित याचिका में, न्यायालय के समक्ष एक प्रश्न उठाया गया था कि क्या शीर्ष न्यायालय को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा पारित आदेश पश्चात शुद्धता पर विचार करना चाहिए, जब उन्होंने मुख्यमंत्री और पर्यावरण मंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी देने से इनकार कर दिया था, जब वे 'ताज हेरिटेज ऑरिडोर प्रोजेक्ट' में जिम्मेदार पाए गए थे। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि न्यायपालिका वहां कदम उठा सकती है जहां वह विधायिका या कार्यपालिका की ओर से किए गए कार्यों को अवैध या असंवैधानिक मानती है।

112. सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बनाम भारत संघ और एक अन्य ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 3277 में, याचिकाकर्ता द्वारा जनहित में दो रिट याचिकाएं दायर की गई थीं, जिसमें ई. एस. एस. ओ. (भारत में उपक्रम का अधिग्रहण) अधिनियम, 1974, बर्मा शेल (भारत में उपक्रम का अधिग्रहण) अधिनियम, 1976 और कैल्टेक्स (कैल्टेक्स ऑयल रिफाइनिंग इंडिया लिमिटेड के शेयरों का अधिग्रहण और भारत में कैल्टेक्स इंडिया लिमिटेड के लिए सभी उपक्रमों) अधिनियम, 1977 के प्रावधानों के विपरीत और उल्लंघन के रूप में संसदीय अनुमोदन या मंजूरी के बिना हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकांश शेयरों को निजी पक्षों को बेचने के सरकार के निर्णय पर प्रश्न उठाया गया था। न्यायालय ने तब तक याचिकाओं को बरकरार रखा जब तक कि कानूनों में उचित संशोधन नहीं किया जाता।

113. ये कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने जनहित याचिकाओं का दायरा बढ़ाया और इस तरह यह सुनिश्चित करने के लिए याचिकाओं पर विचार किया कि राज्य के शासन में, पारदर्शिता है और सार्वजनिक हित को छोड़कर किसी भी प्रतिकूल विचारों को ध्यान में नहीं रखा जाए। लोक प्रशासन में ईमानदारी या न्यायालयों द्वारा

सार्वजनिक जीवन में किए गए भ्रष्टाचार से संबंधित इन मामलों को जनहित याचिका के तीसरे चरण में रखा जा सकता है।

114. हम कुछ ऐसे मामलों से भी निपटना चाहेंगे जहां न्यायालय ने कार्यकारियों और विधायिका को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि मौजूदा कानूनों को पूरी तरह से लागू किया जाए।

115. परीणा स्वरूप बनाम भारत संघ (2008) 13 स्केल 84 में, इस न्यायालय के बार के सदस्य ने एक जनहित याचिका दायर की जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की विभिन्न धाराओं को संविधान के अधिकारातीत घोषित करने की मांग की गई क्योंकि वे मामलों को तय करने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान नहीं करते हैं, लेकिन सदस्यों और अध्यक्ष का चयन राजस्व सचिव की अध्यक्षता वाली चयन समिति द्वारा किया जाता है। याचिकाकर्ता के अनुसार, एल. चंद्रकुमार बनाम भारत संघ और अन्य (1997) 3 एस. सी. सी. 261 के मामले के बाद संविधान द्वारा परिकल्पित शक्तियों के पृथक्करण को कमजोर करता है।

116. हमने अपनी न्यायालयों द्वारा तय किए गए पहले, दूसरे और तीसरे चरण की जनहित याचिकाओं की व्यापक तस्वीर देने का प्रयास किया है।

117. हम अन्य न्यायिक प्रणालियों में जनहित याचिका के विकास पर संक्षेप में चर्चा करना चाहेंगे।

<u>अन्य न्यायिक प्रणालियों अर्थात् संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में जनहित याचिका का विकास।</u>

<u>ऑस्ट्रेलिया</u>

118. ऑस्ट्रेलिया में भी पर्यावरण की रक्षा के लिए, ऑस्ट्रेलियाई न्यायालय ने 'पीड़ित व्यक्ति' के सिद्धान्त को नरम कर दिया है।

191. ऑस्ट्रेलिया में, जनहित याचिका पर्यावरण की रक्षा करने का एक तरीका रहा है। न्यायालयों ने 'जनहित याचिका' की परिभाषा नहीं दी है, लेकिन ओशलैक बनाम रिचमंड रिवर काउंसिल (1998) 193 सी. एल. आर. 72: (1998) 152 ए. एल. आर. 83 में, ऑस्ट्रेलिया के उच्च न्यायालय (शीर्ष न्यायालय) ने अवधारणा को बरकरार रखा और आवश्यक आवश्यकताओं को इंगित किया। मैकहग जे. ने निचली न्यायालय से स्टीन जे. को उद्धृत कियाः

> "संक्षेप में, मुझे लगता है कि मुकदमेबाजी को उचित रूप से जनहित याचिका के रूप में वर्णित किया गया है। चुनौती का आधार तर्क योग्य था, जो गम्भीर और महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाता था जिसके परिणामस्वरूप लुप्तप्राय जीवों के संरक्षण से संबंधित नए प्रावधानों की महत्वपूर्ण व्याख्या होती थी। आवेदन निरंतर विवाद के बीच सार्वजनिक रूप से कुख्यात साइट से संबंधित था। श्री ओशलैक को पर्यावरण कानून को बनाए रखने और लुप्तप्राय जीवों के संरक्षण की सार्थक उद्देश्य के अलावा कुछ भी लाभ नहीं हुआ।"

120. न्यायालय के लिए यह महत्वपूर्ण था कि याचिकाकर्ता का पर्यावरण की रक्षा के बताए गए उद्देश्य के अलावा कोई अन्य उद्देश्य नहीं था। इसलिए ऑस्ट्रेलिया में परीक्षण यह प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता को जनहित याचिका दायर करते समय किसी भी तरह से लाभ नहीं होना चाहिए।

<u>संयुक्त राज्य अमेरिका</u>

121. अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से अफ्रीकी मूल के अश्वेत अमेरिकियों तक पहुंचने के संवैधानिक दायित्व को महसूस किया। न्यायालयों की शिल्प कौशल और नवाचार ओलिवर ब्राउन बनाम टोपेका 347 यू. एस. 483, 489-493 (1954) के शिक्षा बोर्ड में यू. एस. सुप्रीम कोर्ट के सबसे प्रसिद्ध पथ-प्रदर्शक निर्णयों में से एक में परिलक्षित होता है।

शायद, इससे संवैधानिक दायित्व और लक्ष्य पूरा हो जायेगा। इस मामले में, न्यायालयों ने अपनी जांच की है और फैसले में यह देखा गया है कि "हमारी अपनी जांच के साथ सशस्त्र" न्यायालयों ने कहा कि अफ्रीकी मूल के अमेरिकियों सहित सभी अमेरिकी सभी सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययन कर सकते हैं। यह अमेरिकी न्यायपालिका के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण विकास था।

122. अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने एसोसिएशन ऑफ डेटा प्रोसेसिंग सर्विस ऑर्गनाइजेशन बनाम विलियम बी. कैंप 397 यू. एस. 150 (1970) में अधिस्थिति के पारंपरिक नियम को खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि जब भी किसी वादी को "वास्तव में" - "आर्थिक या अन्यथा" चोट लगती है, तो उसे अधिस्थिति की अनुमति दी जा सकती है।

123. एक अन्य प्रसिद्ध मामले में ऑलिव बी. बैरोज़ बनाम लियोला जैक्सन 346 यू. एस. 249 (1953), 73 एस. सी. टी. 1031 न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में टिप्पणी कीः

> "लेकिन वर्तमान मामले में, हम एक अनूठी स्थिति का सामना कर रहे हैं जिसमें यह राज्य की न्यायालय की कार्रवाई है जिसके परिणामस्वरूप संवैधानिक अधिकारों का हनन हो सकता है और जिसमें जिन व्यक्तियों के अधिकारों का दावा किया गया है उनके लिए किसी भी न्यायालय के समक्ष अपनी शिकायत प्रस्तुत करना असंभव नहीं तो कठिन जरूर होगा। इस मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में, हमारा मानना है कि वे कारण जो दूसरे के अधिकारों को बढ़ाने के लिए खड़े होने से इनकार करने वाले हमारे नियम को रेखांकित करते हैं, जो कि केवल अभ्यास का नियम है, मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की

आवश्यकता से अधिक है, जिन्हें नुकसान की कार्रवाई को बनाए रखने की अनुमति देकर अस्वीकार कर दिया जाएगा।"

124. पर्यावरण के मामलों में, यू. एस. सुप्रीम कोर्ट ने रुख को नरम कर दिया है और पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्पित संगठनों को मामलों से लड़ने की अनुमति दी है, भले ही ऐसे समाज सीधे कार्रवाई द्वारा सशस्त्र नहीं हैं।

125. संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम छात्र चुनौती नियामक एजेंसी प्रक्रिया (एस. सी. आर. ए. पी.) 412 यू. एस. 669 (1973) में, न्यायालय ने छात्रों के एक समूह को रेलमार्ग की कार्रवाई को चुनौती देने की अनुमति दी, जिससे पर्यावरण को नुकसान होता।

126. पॉल जे. ट्रैफिकेंट बनाम मेट्रोपॉलिटन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी 409 यू. एस. 205 (1972) में न्यायालय ने कहा कि गैर-गोरों के प्रति एक मकान मालिक की नस्लीय भेदभावपूर्ण प्रथाओं ने वास्तव में वादी, एक अपार्टमेंट परिसर के दो किरायेदारों को "एक एकीकृत समुदाय में रहने के सामाजिक लाभों" से वंचित करके चोट पहुंचाई।

127. इसी तरह, संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने एक अभियोक्ता को कुछ स्थितियों में किसी तीसरे पक्ष द्वारा की गई चोटों को चुनौती देने के लिए अधिस्थिति की अनुमति प्रदान की है, जिसके साथ उसका "घनिष्ठ" संबंध है।

128. थॉमस ई. सिंगलटन बनाम जॉर्ज जे. एल. वुल्फ 428 यू. एस. 106 (1976) में, न्यायालय ने गर्भपात को सीमित करने वाले कैपलिन बनाम ड्राइसडेल अधिनियम में दो चिकित्सकों को अधिस्थिति की अनुमति प्रदान की। इसी तरह कैपलिन बनाम ड्राईस्डेल 491 यू. एस. 617, 623-24 एन. 3 (1989) में, न्यायालय ने एक वकील को एक दवा ज़ब्ती कानून को चुनौती देने के लिए अधिस्थिति की अनुमति प्रदान की जो उसके मुवक्किल को वकील बनाए रखने के साधनों से वंचित कर देगा।

129. सर्वोच्च न्यायालय ने भी संगठनात्मक अधिस्थिति की अनुमति प्रदान की है। रॉबर्ट वार्थ बनाम इरा सेल्डिन 422 यू. एस. 490, 511 (1975) में, न्यायालय ने घोषणा की कि "खुद को नुकसान की अनुपस्थिति में भी, एक संघ पूरी तरह से अपने सदस्यों के प्रतिनिधि के रूप में खड़ा हो सकता है। उन्होंने कहा, "इस फैसले के दूरगामी परिणाम थे। जेम्स बी. हंट बनाम वाशिंगटन राज्य ऐप्पल विज्ञापन आयोग, 432 यू. एस. 333, 343 (1977) में, न्यायालय ने संगठनात्मक अधिस्थिति के लिए मानकों को विस्तृत किया जहां एक संगठन या संघ अपने सदस्यों की ओर से मुकदमा करने के लिए खड़ा है जबः(ए) इसके सदस्यों को अन्यथा अपने स्वयं के अधिकार में मुकदमा करने के लिए अनुमति होगी; (बी) जिन हितों की वह रक्षा करना चाहता है वे संगठन के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हैं; (सी) न तो दावा किया गया है, न ही अनुरोध की गई राहत, मुकदमे में व्यक्तिगत सदस्यों की भागीदारी की आवश्यकता है।

<u>इंग्लैंड</u>

130. इंग्लैंड में पी. आई. एल. का उपयोग अपेक्षाकृत सीमित रहा है। पी. आई. एल. में सीमित विकास अधिस्थिति के नियमों को व्यापक बनाने के माध्यम द्वारा हुआ है।

<u>अधिस्थिति के व्यापक नियम</u>

131. सार्वजनिक हित की पुष्टि की सुविधा के लिए री रीड, बोवेन एंड कंपनी (1887) 19 क्यूबीडी 174 में, अंग्रेजी न्यायपालिका ने अधिस्थिति के व्यापक नियम निर्धारित किए। अधिस्थिति के पारंपरिक नियम के तहत, न्यायिक निवारण मात्र एक 'पीड़ित व्यक्ति' के लिए उपलब्ध था, जिसे कानूनी शिकायत का सामना करना पड़ा है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध एक निर्णय सुनाया गया है जिसने उसे गलत तरीके से किसी चीज़ से वंचित कर दिया है या गलत तरीके से उसे कुछ देने अस्वीकार करना कर दिया है

किसी चीज़ पर उसके शीर्षक को गलत तरीके से प्रभावित किया।" यद्यपि पारंपरिक नियम अब अंग्रेजी न्यायालयों में अधिस्थिति को नियंत्रित नहीं करता है।

132. सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित अंग्रेजी न्यायाधीशों में से एक लॉर्ड डेनिंग ने अपने सुझाव के साथ अंग्रेजी न्यायालयों में अधिस्थिति के अधिकार को व्यापक बनाने की शुरुआत की कि 'पीड़ित व्यक्ति' शब्द व्यापक महत्व के हैं और इन्हें प्रतिबंधात्मक व्याख्या के अधीन नहीं किया जाना चाहिए। गाम्बिया के अटॉर्नी-जनरल बनाम पियरे सर एन 'जी (1961) एसी 617।

133. ब्लैकबर्न मामलों ने निजी अधिकार के भंग के लिए सार्वजनिक अधिकारियों के विरुद्ध व्यक्तियों द्वारा लाए गए विशेषाधिकार रिट के माध्यम द्वारा उपचार की मांग करने वाली कार्रवाइयों में अधिस्थिति के नियम को व्यापक बना दिया। (उदाहरण के लिए, परमादेश, निषेध, और उत्प्रेषण)। ब्लैकबर्न मानक के तहत, गलत नीतिगत निर्णय लेने में एक सरकारी अधिकारी की कार्रवाई द्वारा "कोई भी व्यक्ति जो प्रतिकूल रूप द्वारा प्रभावित था", विशेषाधिकार रिट से माध्यम द्वारा उपचार की मांग के लिए न्यायालय के समक्ष अधिस्थिति के लिए पात्र था -रेजिना बनाम महानगर के पुलिस आयुक्त, एकपक्षीय ब्लैकबर्न [1968] 2 डब्ल्यू. एल. आर. 893 ("ब्लैकबर्न।")।

134. ब्लैकबर्न में, अपील न्यायालय ने ब्लैकबर्न को जुआ क्लबों के खिलाफ सट्टेबाजी और जुआ क़ानून लागू करने के लिए पुलिस आयुक्त को बाध्य करने के लिए परमादेश की रिट मांगने के लिए सुने जाने का अधिकार दिया।

135. ब्लैकबर्न ॥ में, अपील न्यायालय ने एक आम बाजार में शामिल होने के लिए सरकार के निर्णय को चुनौती देने के लिए ब्लैकबर्न के अधिस्थिति में कोई दोष नहीं पाया। ब्लैकबर्न बनाम अटॉर्नी-जनरल [1971] 1 डब्ल्यू. एल. आर. 1037)।

136. ब्लैकबर्न III में, अपील न्यायालय ने ब्लैकबर्न को अश्लील प्रकाशनों के विरुद्ध कानूनों को लागू करने के लिए मेट्रोपॉलिटन पुलिस को मजबूर करने के लिए परमादेश की एक रिट की मांग करने के लिए अधिस्थिति प्रदान किया। रेजिना वी. मेट्रोपोलिस की पुलिस आयुक्त, पूर्व एकपक्षीय ब्लैकबर्न [1973] क्यू. बी. 241।

137. ब्लैकबर्न IV में, अपील न्यायालय ने ब्लैकबर्न को अश्लील फिल्मों के संबंध में अपनी सेंसरशिप शक्तियों का ठीक से उपयोग करने में विफल रहने के लिए ग्रेटर लंदन काउंसिल में निर्देशित निषेध की रिट की मांग करने के लिए अधिस्थिति प्रदान किया। रेजिना बनाम ग्रेटर लंदन काउंसिल पूर्व एकपक्षीय ब्लैकबर्न [1976] 1 डब्ल्यू. एल. आर. 550।

138. अंग्रेजी न्यायपालिका रिलेटर दावों के माध्यम द्वारा समाधान की मांग करने वाली कार्रवाइयों के लिए अधिस्थिति के इस व्यापक नियम को लागू करने में हिचकिचा रही थी, - संबंधित दावे जो अटॉर्नी-जनरल द्वारा सार्वजनिक अधिकार के उल्लंघन के समाधान करने के लिए लाए गए उपाय हैं। (उदाहरण के लिए घोषणा और निषेधाज्ञा)। प्रारंभ में, लॉर्ड डेनिंग ने संबंधित दावे के माध्यम द्वारा उपचार की मांग करने वाली कार्रवाइयों के लिए विशेषाधिकार रिट के माध्यम द्वारा उपचार की मांग करने वाली कार्रवाई में अधिस्थिति के व्यापक नियम का विस्तार किया। अटॉर्नी-जनरल एक्स रिले मैकविर्टर इंडिपेंडेंट ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी, (1973) क्यू. बी. 629 में न्यायालय ने निर्धारित किया कि, "अंतिम उपाय में, यदि अटॉर्नी-जनरल किसी उचित मामले में छुट्टी देने से इनकार कर देता है, या अनुचित तरीके से या अनुचित तरीके से छुट्टी देने में देरी करता है, या उसकी मशीनरी बहुत धीमी गति से काम करती है, तो जनता का एक सदस्य जिसके पास पर्याप्त रुचि है वह स्वयं न्यायालय में आवेदन कर सकता है। इस नियम को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा गौरीट बनाम डाकघर कर्मचारियों के संघ [1978] ए. सी. 435 में तुरंत उलट दिया गया था। इस

मामले में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कहा कि संबंधित दावों में, अटॉर्नी जनरल को यह तय करने में पूर्णतः विवेकाधीन है कि किसी मामले को अनुमति दी जाए या नहीं। इस प्रकार, अंग्रेजी न्यायपालिका ने संबंधित दावों के माध्यम द्वारा समाधान की मांग करने वाले व्यक्ति सुने जाने का अधिकार प्रदान नहीं किया।

139. अंत में, 1978 में आदेश 53 के माध्यम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के नियमों में एक संशोधन ने संबंधित दावों पर अधिस्थिति के एक व्यापक नियम को लागू करने में अंग्रेजी न्यायपालिका की हिचकिचाहट को दूर कर दिया। आदेश 53 ने विशेषाधिकार रिट के माध्यम द्वारा समाधान की मांग करने वाले दोनों कार्यों और संबंधित दावों के माध्यम द्वारा समाधान की मांग करने वाले कार्यों के लिए अधिस्थिति के व्यापक नियम को लागू किया। आदेश 53 के नियम 3 (5) में कहा गया है कि न्यायालय न्यायिक समीक्षा के लिए अनुमति तब तक नहीं देगा जब तक कि वह यह नहीं मानता कि आवेदक का उस मामले में पर्याप्त हित है जिससे आवेदक संबंधित है। आदेश 53, एस. यू. पी. टी. सी. टी. के नियम (1981)। अंतर्देशीय राजस्व आयुक्त नेशनल फेडरेशन ऑफ सेल्फ-एम्प्लॉयड एंड स्मॉल बिजनेस लिमिटेड [1982] ए. सी. 617 में, न्यायालय ने समझाया कि "निष्पक्षता और न्याय ऐसे परीक्षण हैं जिन्हें लागू किया जाना चाहिए" यह निर्धारित करते समय कि क्या किसी पार्टी के पास पर्याप्त हित हैं।

140. रेजिना बनाम पर्यावरण राज्य सचिव में, एकपक्षीय रोज़ थिएटर ट्रस्ट कंपनी (1990) 1 क्यू.बी. 504 में, न्यायालय ने विस्तार से बताया कि पर्याप्त ब्याज पाने के लिए "प्रत्यक्ष वित्तीय या कानूनी हित की आवश्यकता नहीं है"। इस प्रकार, आदेश 53 में सन्निहित अधिस्थिति के नए नियम के तहत, व्यक्ति सार्वजनिक अधिकारियों के कार्यों को चुनौती दे सकते हैं यदि उनके पास "पर्याप्त हित" पाया जाता है -एक लचीला मानक।

<u>दक्षिण अफ्रीका</u>

141. दक्षिण अफ्रीका के संविधान को "समाज को एक ऐसे समाज में बदलने की प्रतिबद्धता के साथ अपनाया गया है जिसमें मानव गरिमा, स्वतंत्रता और समानता होगी।" देखें: सूब्रमनी बनाम स्वास्थ्य मंत्री, क्वाज़ुलु-नताल, 1998 (1) एसए 765 (सीसी), पी.5। इस प्रकार, न्याय तक पहुंच में सुधार करना इस संविधान के अधिदेश के अंतर्गत आता है। इस उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए, दक्षिण अफ्रीकी कानूनी ढांचा अधिस्थिति के व्यापक नियमों को निर्धारित करके और अभिवचन आवश्यकताओं में ढील देकर जनहित याचिका के प्रति एक अनुकूल रुख अपनाता है।

(ए) **<u>अधिस्थिति के व्यापक नियम</u>**

142. संविधान की धारा 38 मोटे तौर पर अधिकारों के विधेयक में किसी अधिकार के उल्लंघन के आरोपों के लिए एक सक्षम न्यायालय से संपर्क करने का अधिकार देती है:

> "(ए) कोई भी अपने हित में काम कर रहा है;
>
> (बी) किसी अन्य व्यक्ति की ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति जो अपने नाम पर कार्य नहीं कर सकता;
>
> (सी) व्यक्तियों के समूह या वर्ग के सदस्य के रूप में या उनके हित में कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति;
>
> (डी) सार्वजनिक हित में कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति;
>
> (ई) अपने सदस्यों के हित में कार्य करने वाला एक संघ।"

143. वर्ग की कार्रवाइयों और तृतीय-पक्ष की कार्रवाइयों को स्पष्ट रूप से अनुमति देते हुए, धारा 38 संवैधानिक दावों के लिए अधिस्थिति के व्यापक नियमों को निर्धारित करती है, जो कि धारा 38 की भाषा की व्याख्या करते है,

संवैधानिक न्यायालय ने फेरेरा बनाम लेविन एन. ओ. और अन्य 1996 (1) एस. ए. 984 (सी. सी.), पृष्ठ 241 में विस्तार से बताया कि संवैधानिक दावों के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण लागू किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संवैधानिक अधिकारों को संरक्षण का पूरा उपाय दिया गया है जिसके वे हकदार हैं। एक अलग सहमति वाले फैसले द्वारा उक्त फैसले में, न्यायमूर्ति ओ 'रेगन ने सुझाव दिया कि सभी "सार्वजनिक चरित्र के मुकदमेबाजी" के लिए "अधिस्थिति के लिए एक व्यापक जाल" का विस्तार किया जाना चाहिए।

(बी) **<u>वादों की औपचारिक आवश्यकताओं में ढील देना</u>**

144. संवैधानिक न्यायालय को उचित मामलों में औपचारिक अभिवचन आवश्यकताओं में ढील देने के लिए तत्पर रहा है। एस. वी. त्वाला (दक्षिण अफ्रीकी मानवाधिकार आयोग हस्तक्षेप), 2000 (1) एस. ए. 879 में, न्यायालय के अध्यक्ष ने निर्देश दिया कि अपील करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने में अपनी हताशा की शिकायत करने वाले एक कैदी से प्राप्त एक हस्तलिखित पत्र को अपील करने की अनुमति के लिए आवेदन के रूप में माना जाए।

145. शिनवा और अन्य बनाम वोक्सवैगन ऑफ साउथ अफ्रीका (पीटीवाई) लिमिटेड 2003 (4) एसए 390 (सीसी), पी. 8 में न्यायालय ने त्वाला सिद्धान्त को मजबूत किया कि जनहित याचिका में "रूप को सार के लिए रास्ता देना चाहिए"। न्यायालय ने समझाया कि "आम व्यक्तियों द्वारा तैयार किए गए अभिवचनों को उदारता से और वादकारी के लिए सबसे अनुकूल माना जाना चाहिए। आम वादियों को अपने मामले की प्रस्तुति में वकीलों के लिए अपेक्षित सटीकता, कौशल और परिशुद्धता के समान मानक पर नहीं रखा जाना चाहिए। इस तरह के अभिवचनों का अर्थ निकालने में, अभिवचन के उद्देश्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए जो न मात्र

अभिवचनों की सामग्री से बल्कि उस संदर्भ से भी एकत्र किया गया है जिसमें अभिवचन तैयार किया गया है।"

<u>पड़ोसी देशों पर जनहित याचिका का प्रभाव</u>

146. भारत में जनहित याचिकाओं के विकास का पड़ोसी देशों जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान और अन्य देशों की न्यायिक प्रणालियों पर प्रभाव पड़ा है।

<u>पाकिस्तानः</u>

147. 31 जुलाई, 2009 को इस्लामाबाद में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया ऐतिहासिक फैसले द्वारा, सिंध उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन द्वारा अपने सचिव के माध्यम से दायर 2009 की संविधान याचिका संख्या 9 वाली जनहित याचिका और नदीम अहमद एडवोकेट द्वारा दायर 2009 की संविधान याचिका संख्या 8, दोनों याचिकाएं सचिव, कानून और न्याय मंत्रालय, इस्लामाबाद और अन्य के माध्यम से पाकिस्तान संघ के खिलाफ दायर की गईं, पूरी वरिष्ठ न्यायपालिका जिसे पिछले राजनीतिक शासन द्वारा बर्खास्त कर दिया गया था, अब बहाल कर दी गई है।

148. हाल ही में 16 दिसंबर, 2009 को पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के सभी 17 न्यायाधीशों द्वारा 2007 की संविधान याचिका संख्या 76 से 80 और 2009 की 59 पर एक पथप्रदर्शक निर्णय दिया गया और 2009 की एक अन्य सिविल अपील संख्या 1094 के भी दूरगामी निहितार्थ हैं।

149. इस निर्णय से, राष्ट्रीय सुलह अध्यादेश (संख्या XV) 2007 को चुनौती दी गई, जिसके द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 और लोक अभ्यावेदन अधिनियम, 1976 और 1999 के राष्ट्रीय जवाबदेही अध्यादेश से संशोधन किए गए। राष्ट्रीय जवाबदेही अध्यादेश, 1999 (संक्षेप में, एन. ए. ओ.) को

संवैधानिक प्राधिकरणों और सत्ता में अन्य प्राधिकरणों द्वारा किए गए अपराधों के परिणामों की प्रतिरक्षा देने के लिए बनाया गया था और (एन. आर. ओ.) को आरम्भतः ही अमान्य घोषित कर दिया गया था क्योंकि यह संविधान के 4, 8, 25, 62 (एफ), 63 (आई) (पी), 89, 175 और 227 सहित संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है। यह निर्णय भी काफी हद तक जनहित में दिया गया था।

150. पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सामान्य सचिव, पश्चिम पाकिस्तान नमक खनिक श्रम संघ (सी. बी. ए.) खेवरा, झेलम बनाम निदेशक, उद्योग और खनिज विकास, पंजाब, लाहौर में दिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय में 1994 में एस. सी. एम. आर. 2061 (पाकिस्तान का सर्वोच्च न्यायालय) में 1993 के मानवाधिकार मामले संख्या 120 में 12 जुलाई, 1994 को इस न्यायालय के निर्णयों की इच्छाओं के आधार पर महत्वपूर्ण निर्देश दिए।

151. उक्त याचिका में याचिकाकर्ताओं ने निवासियों के स्वच्छ और अप्रदूषित पानी के अधिकारों को लागू करने की मांग की। उनकी आशंका थी कि यदि खनिकों को अपनी गतिविधियों को जारी रखने की अनुमति दी जाती है, जो जलग्रहण क्षेत्र में विस्तारित हैं, तो जलमार्ग, जलाशय और पाइपलाइन दूषित हो जाएंगे। न्यायालय के अनुसार, इस दुनिया में पानी को जीवन का स्रोत माना गया है। पानी के बिना कोई जीवन नहीं हो सकता। इतिहास इस बात की गवाही देता है कि अकाल और पानी की कमी के कारण सभ्यता गायब हो गई है, हरी-भरी भूमि रेगिस्तान में बदल गई है शुष्कता न केवल मनुष्य, बल्कि पशु जीवन को भी पूरी तरह से नष्ट कर रही है। इसलिए, जल, जो जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक है, यदि प्रदूषित या दूषित हो जाता है, तो मानव अस्तित्व के लिए गम्भीर खतरा पैदा करेगा।

152. न्यायालय ने प्रदूषण और पर्यावरण क्षरण पैदा करने वाले कारखाने के कामकाज को रोकने सहित महत्वपूर्ण निर्देश दिए।

153. एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू जो इस मामले में तय किया गया है, वह था 'पीड़ित व्यक्ति' की परिभाषा को व्यापक बनाना। न्यायालय ने कहा कि जनहित याचिका में, प्रक्रियात्मक पेंच और पीड़ित व्यक्ति होने के प्रतिबंध और इसी तरह की अन्य तकनीकी आपत्तियां न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बाधित नहीं कर सकती हैं। उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि न्यायालय के पास अनुच्छेद 183 (3) के तहत तथ्य के प्रश्न की जांच करने के साथ-साथ साक्ष्य दर्ज करके स्वतंत्र रूप से जांच करने की व्यापक शक्ति है।

154. एक अन्य महत्वपूर्ण मामले में सुश्री शेहला जिया बनाम वापदा पी. एल. डी. 1994 सुप्रीम कोर्ट 693, मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उक्त याचिका में स्ट्रीट नंबर 35, एफ-6/1, इस्लामाबाद के चार निवासियों ने एफ-6/1, इस्लामाबाद में एक ग्रिड स्टेशन के निर्माण के विरुद्ध डब्ल्यूएपीडीए का विरोध किया। इस आशय का एक पत्र 15.1.1992 को अध्यक्ष को लिखा गया था जिसमें कथित रूप से एक आवासीय इलाके के हरित क्षेत्र में स्थित ग्रिड स्टेशन के निर्माण के संबंध में क्षेत्र के निवासियों की शिकायत और आशंकाओं को व्यक्त किया गया था। उन्होंने बताया कि ग्रिड स्टेशन पर उच्च वोल्टेज पारेषण लाइनों की उपस्थिति से विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र के निवासियों, विशेष रूप से बच्चों, कमजोर और आसपास रहने वाले धोबी-घाट परिवारों के लिए एक गम्भीर स्वास्थ्य खतरा पैदा करेगा। विद्युत प्रतिष्ठानों और पारेषण लाइनों की उपस्थिति भी नागरिकों के लिए विशेष रूप से उन बच्चों के लिए अत्यधिक खतरनाक होगी जो क्षेत्र में बाहर खेलते हैं। यह हरित पट्टी को नुकसान पहुँचाएगा और पर्यावरण को प्रभावित करेगा। यह भी आरोप लगाया गया था कि यह इस्लामाबाद में योजना के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है जहां पर्यावरण और सौंदर्य कारणों से हरित पट्टियों को शहर का एक आवश्यक घटक माना जाता है।

155. उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जहां नागरिकों का जीवन खराब होता है, वहां जीवन की गुणवत्ता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है और स्वास्थ्य संबंधी खतरे बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। उच्चतम न्यायालय अपने न्यायिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए प्रदूषण और पर्यावरण क्षरण पैदा करने वाली ऐसी इकाइयों के कामकाज को रोकने की सीमा तक राहत दे सकता है।

<u>श्री लंका</u>

156. जनहित याचिका का अन्य देशों पर बहुत प्रभाव पड़ा है। बुलानकुलमा और छह अन्य बनाम सचिव, औद्योगिक विकास मंत्रालय और सात अन्य (एप्पावाला मामला) में, श्रीलंका के सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका में महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उक्त मामले में, श्रीलंका के कृषि समृद्ध उत्तर मध्य प्रांत के एप्पावाला में रॉक फॉस्फेट भंडार के तेजी से दोहन के लिए सरकार और निजी कंपनी के बीच खनिज निवेश समझौता किया गया था - उच्च तीव्रता वाले खनन संचालन के साथ-साथ त्रिंकोमाली तट पर एक प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना की गई थी जो फॉस्फोरिक और सल्फ्यूरिक एसिड का उत्पादन करेगा। क्षेत्र के छह निवासियों, जिनकी कृषि भूमि प्रभावित होने वाली थी, ने जनहित में न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की। याचिका में कहा गया था कि यह परियोजना सार्वजनिक उद्देश्य के लिए नहीं थी, बल्कि एक निजी कंपनी के लाभ के लिए थी और इससे श्रीलंका को पर्याप्त आर्थिक लाभ नहीं होगा। याचिकाकर्ताओं ने संविधान के विभिन्न प्रावधानों के तहत अपने मौलिक अधिकार के आसन्न उल्लंघन का दावा किया। न्यायालय ने एम. सी. मेहता बनाम कमल नाथ (1997) 1 एस. सी. सी. 388 के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका और हमारे देश में लागू सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत को लागू किया। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकार को बरकरार रखा। प्रतिवादी को एप्पावाला फॉस्फेट जमा से संबंधित किसी भी अनुबंध में प्रवेश करने से रोक दिया गया था।

न्यायालय ने याचिका को स्वीकार कर लिया और प्रतिवादी को याचिकाकर्ताओं को हर्जाना देने का निर्देश दिया गया। श्रीलंका के सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में महत्वपूर्ण निर्देश देकर पर्यावरण क्षरण की रक्षा की।

<u>नेपालः</u>

157. नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने 1992 की रिट याचिका संख्या 35 में सूर्य प्रसाद शर्मा ढुंगले बनाम गोदावरी मार्बल इंडस्ट्रीज में महत्वपूर्ण निर्देश पारित किए। याचिका में आरोप लगाया गया था कि गोदावरी संगमरमर उद्योग गोदावरी वन को गम्भीर पर्यावरणीय क्षरण का कारण बन रहा है और इसके आसपास जो प्राकृतिक भव्यता से समृद्ध है और ऐतिहासिक और धार्मिक प्रतिष्ठापन को प्रतिवादी द्वारा नष्ट किया जा रहा है। याचिका में यह उल्लेख किया गया था कि प्रतिवादी गोदावरी मार्बल इंडस्ट्रीज की अवैध गतिविधियों से भारी सार्वजनिक नुकसान हुआ है।

158. नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय ने पर्यावरण और पारिस्थितिकी के क्षरण की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए। न्यायालय ने सतत विकास की अवधारणा को अपनाया।

159. भारतीय न्यायालयों ने संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों के समूह या वर्ग हित मुकदमेबाजी से कुछ प्रेरणा ली होगी, लेकिन जैसा कि हम अब देखते हैं कि जनहित याचिका का आकार मुख्य रूप से स्वदेशी रूप से विकसित न्यायशास्त्र है।

160. विभिन्न पहलुओं और विभिन्न शाखाओं में विकसित जनहित याचिका अद्वितीय है। भारतीय न्यायालयों ने अपनी न्यायिक शिल्प कौशल, रचनात्मकता और समाज के वंचित, भेदभावपूर्ण और अन्यथा कमजोर वर्गों को न्याय प्रदान करने के आग्रह से जनहित याचिका के लेबल में दायर

मामलों से निपटने के दौरान मानव जीवन के लगभग हर पहलू को छुआ है। भारत और न्यायालयों द्वारा दिए गए कुछ आवश्यक और महत्वपूर्ण निर्देशों के कारण भारत के उच्च न्यायालयों की विश्वसनीयता में जबरदस्त वृद्धि हुई है। जीवन और स्वतंत्रता की नई परिभाषा देकर समाज के गरीब वर्गों की मदद करने और पारिस्थितिकी, पर्यावरण और वनों की रक्षा करने में न्यायालयों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है।

<u>जनहित याचिका का दुरुपयोग:</u>

161. दुर्भाग्य से, हाल ही में, यह देखा गया है कि इस तरह के एक महत्वपूर्ण क्षेत्राधिकार, जिसे न्यायालयों द्वारा बहुत सावधानीपूर्वक तैयार, निर्मित और पोषित किया गया है, परोक्ष उद्देश्यों के साथ कुछ याचिकाएं दायर करके खुलेआम दुरुपयोग किया जा रहा है। हम समझते हैं कि समय आ गया है जब वास्तविक और प्रामाणिक जनहित याचिकाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जबकि तुच्छ जनहित याचिकाओं को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

162. हमारी सुविचारित राय में, हमें इस देश के लोगों के व्यापक हित में इस महत्वपूर्ण क्षेत्राधिकार की रक्षा और संरक्षण करना होगा, लेकिन हमें मौद्रिक और गैर-आर्थिक आधार पर इसके दुरुपयोग को रोकने और ठीक करने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

163. बाल्को कर्मचारी संघ (पंजीकृत) बनाम भारत संघ और अन्य एआईआर 2002 एससी 350 में, इस न्यायालय ने माना कि हाल के दिनों में, जनहित याचिका के दुरुपयोग के मामले बढ़ रहे हैं। तदनुसार, न्यायालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई रणनीतियाँ तैयार की हैं कि जनहित याचिका के आकर्षक ब्रांड नाम को शरारत के संदिग्ध उत्पादों के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सबसे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका में "सच्चाई से काम करने

वाले" व्यक्तियों तक ही सीमित अधिकार में रखा है।" दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय ने तुच्छ और परेशान करने वाली जनहित याचिकाओं के विरुद्ध निवारक के रूप में "अनुकरणीय हर्जाना" लगाने की मंजूरी दी है। तीसरा, उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालयों को जनहित याचिकाओं पर विचार करने के लिए अधिक चयनात्मक होने का निर्देश दिया है।

164. एस. पी. गुप्ता के मामले (ऊपर) में, इस न्यायालय ने पाया है कि यह उदार मानक व्यक्तियों के प्रामाणिक व्यवहार को सीमित करना महत्वपूर्ण बनाता है। पी. आई. एल. की आड़ में तुच्छ और परेशान करने वाली याचिकाओं पर विचार करने से बचने के लिए, न्यायालय ने व्यक्तियों के दो समूहों को पी. आई. एल. याचिकाओं में खड़े होने से बाहर रखा है। सबसे पहले, सर्वोच्च न्यायालय ने "हस्तक्षेप करने वाले हस्तक्षेपकर्ताओं" को सुने जाने से इनकार कर दिया है। दूसरा, न्यायालय ने व्यक्तिगत लाभ के लिए जनहित याचिका लाने वाले हस्तक्षेपकर्ताओं को सुने जाने से इनकार कर दिया है।

165. छेत्रीय परदुषण मुक्ति संघर्ष समिति (उपरोक्त) में, न्यायालय ने आवेदक का पक्ष इस आधार पर रोक दिया कि आवेदक ने पार्टियों के बीच दुश्मनी से प्रेरित होकर मुकदमा दायर किया था। इस प्रकार, उच्चतम न्यायालय ने न्यायशास्त्र का एक ऐसा निकाय बनाने का प्रयास किया है जो वास्तविक जनहित याचिकाओं को स्वीकार करने के लिए व्यापक और पर्याप्त अधिस्थति प्रदान करता है, लेकिन फिर भी तुच्छ और परेशान करने वाली याचिकाओं को विफल करने के लिए अधिस्थति को सीमित करता है।

166. उच्चतम न्यायालय ने मोटे तौर पर दो तरीकों से निरर्थक जनहित याचिकाओं पर अंकुश लगाने की कोशिश की - एक मौद्रिक और दूसरा, गैर- मौद्रिक। मामलों की पहली श्रेणी यह है कि जहां न्यायालय तुच्छ जनहित हित याचिकाएं दायर करने पर, याचिकाओं को अनुकरणीय हर्जाने के साथ खारिज कर देती है। नीटू बनाम पंजाब राज्य और अन्य

एआईआर 2007 एससी 758 में, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि यह सुनिश्चित करने के लिए अनुकरणीय हर्जाना लगाना आवश्यक है कि संदेश सही दिशा में जाए कि अप्रत्यक्ष उद्देश्य से दायर याचिकाओं को न्यायालयों की मंजूरी नहीं है।

167. एस. पी. आनंद बनाम एच. डी. देवगौड़ा और अन्य ए. आई. आर. 1997 एस. सी. 272 में, न्यायालय ने चेतावनी दी कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जो लोग इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का उपयोग करते हुए अधिस्थिति (लोकस स्टैंडी) नियम से छूट की मांग करते हैं, उन्हें उन क्षेत्रों में नहीं गिरकर न्यायालय का रुख करने में संयम बरतना चाहिए जहां वे अच्छी तरह से परिचित नहीं हैं।

168. संजीव भटनागर बनाम भारत संघ और अन्य ए. आई. आर. 2005 एस. सी. 2841 में, इस न्यायालय ने एक तुच्छ और कष्टप्रद जनहित याचिका दायर करने के लिए एक अधिवक्ता के खिलाफ मौद्रिक जुर्माना लगाकर एक कदम आगे बढ़ाया। न्यायालय ने पाया कि याचिका जनहित से रहित थी, और इसके बजाय इसे "प्रचार हित याचिका" करार दिया।" इस प्रकार, न्यायालय ने रुपये 10,000/- के जुर्माने के साथ याचिका खारिज कर दी।

169. इसी तरह दत्तराज नाथूजी थवारे बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2005) 1 एस. सी. सी. 590 में, सर्वोच्च न्यायालय ने एक तुच्छ और परेशान करने वाली जनहित याचिका दायर करने के लिए बार के एक सदस्य के विरुद्ध उच्च न्यायालय के मौद्रिक दंड की पुष्टि की। इस न्यायालय ने पाया कि याचिका व्यक्तिगत विवाद को बढ़ावा देने के लिए एक छलावरण के अलावा और कुछ नहीं थी। यह देखते हुए कि किसी को भी कुलीन पेशे को बदनाम करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि उच्च न्यायालय द्वारा रु. 25,000 जुर्माना लगाया जाना उचित था। स्पष्ट

रूप से, सर्वोच्च न्यायालय ने तुच्छ और परेशान करने वाली जनहित याचिकाओं के विरुद्ध आर्थिक दंड लगाने को मान्य करने के लिए स्पष्ट उदाहरण स्थापित किया है, विशेष रूप से जब अधिवक्ताओं द्वारा दायर किया जाता है।

170. इस न्यायालय ने, मामलों की दूसरी श्रेणी में, और भी कठोर आदेश पारित किए। चरण लाल साहू और अन्य बनाम ज्ञानी जैल सिंह और एक अन्य ए. आई. आर. 1984 एस. सी. 309 में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि "हल्के-फुल्के और उदासीन" जनहित याचिका दायर करने के लिए "हम दोनों याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध भारी जुर्माना लगाने का आदेश पारित करना उचित होता। यद्यपि "भविष्य के अवसर पर एक अच्छी तरह से स्थापित दावे को शुरू में ही खत्म करने" को रोकने के लिए, न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं पर आर्थिक दंड लगाने के विरुद्ध फैसला किया। पीठ ने कहा, "इस मामले में, इस न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि याचिका लापरवाह, अर्थहीन, अनाड़ी और जनहित के विरुद्ध थी। इसलिए, न्यायालय ने पंजीकरण को न्यायालय की अवमानना अधिनियम के तहत याचिकाकर्ता के विरुद्ध अभियोजन कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने रजिस्ट्री को याचिकाकर्ता द्वारा दायर भविष्य की किसी भी जनहित याचिका पर विचार करने से मना कर दिया, जो इस मामले में एक अधिवक्ता थे।

171. जे. जयललीता बनाम तमिलनाडु सरकार और अन्य (1999) 1 एस. सी. सी. 53 में, इस न्यायालय ने निर्धारित किया कि किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी सार्वजनिक सम्पति के दुरुपयोग या अनुचित उपयोग को चुनौती देने के लिए जनहित याचिका दायर की जा सकती है, जिसमें सत्ता में राजनीतिक पार्टी भी शामिल है, क्योंकि व्यक्तियों के हित को किसी बड़ी सार्वजनिक हित से ऊपर नहीं रखा जा सकता है या उन्हें प्राथमिकता नहीं दी जा सकती है।

172. यह न्यायालय इस बात को लेकर काफी सचेत रहा है कि इस न्यायालय के मंच का किसी के द्वारा व्यक्तिगत लाभ या किसी अप्रत्यक्ष उद्देश्य के लिए दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

173. बाल्को (ऊपर) में, इस न्यायालय ने माना कि बेईमान व्यक्तियों द्वारा अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए क्षेत्राधिकार का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसलिए, न्यायालय को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत लाभ के लिए मंच का दुरुपयोग न किया जाए।

174. दत्तराज नाथूजी थवारे (उपरोक्त) मामले में, इस न्यायालय ने जनहित याचिका की आड़ में न्यायालय के मंच के दुरुपयोग पर अपनी पीड़ा व्यक्त की और कहा कि जनहित याचिका एक ऐसा हथियार है जिससे उपयोग बहुत देखभाल और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए और न्यायपालिका को यह देखने के लिए बेहद सावधान रहना चाहिए कि जनहित के सुंदर पर्दे के पीछे, एक बदसूरत निजी द्वेष, निहित हित और/या प्रचार की मांग छिपी नहीं है। इसका उपयोग नागरिकों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए कानून के शस्त्रागार में एक प्रभावी हथियार के रूप में किया जाना है। न्यायालय को अपनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

175. थावरे के मामले में (ऊपर उल्लिखित), न्यायालय ने बार के एक सदस्य द्वारा दायर जनहित याचिका के विरुद्ध गैर-मौद्रिक दंड लगाने को प्रोत्साहित किया। न्यायालय ने बार काउंसिलों और बार एसोसिएशनों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि बार का कोई भी सदस्य याचिकाकर्ता के रूप में या जनहित याचिका के आकर्षक ब्रांड नाम वाली तुच्छ याचिकाओं को दायर करने में सहायता और/या बढ़ावा देने में पक्षकार न बने। यह निर्देश बार काउंसिल और बार एसोसिएशनों

को तुच्छ और परेशान करने वाली जनहित याचिका दायर करने के दोषी पाए गए सदस्यों को बर्खास्त करने के लिए बाध्य करता है।

176. होलिको पिक्चर्स प्राइवेट प्राइवेट लिमिटेड बनाम प्रेम चंद्र मिश्रा और अन्य ए. आई. आर. 2008 एस. सी. 913 में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी कीः

> 'यह निराशाजनक है कि न्यायालयों के समक्ष शुरू की गई ऐसी बेतुकी कार्यवाहियों के कारण, असंख्य दिन बर्बाद हो जाते हैं, वह समय जो अन्यथा वास्तविक वादियों के मामलों के निपटारे के लिए खर्च किया जा सकता था। हालाँकि हम पी. आई. एल. की प्रशंसनीय अवधारणा को बढ़ावा देने और विकसित करने और गरीबों, अज्ञानी, उत्पीड़ित और जरूरतमंदों के प्रति अपनी सहानुभूति बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, जिनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन और अतिक्रमण किया जाता है और जिनकी शिकायतों पर किसी का ध्यान नहीं जाता है, जिनका प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता है और जिन्हें सुना नहीं जाता है। फिर भी हम अपनी राय व्यक्त करने से बच नहीं सकते हैं, जबकि सैकड़ों करोड़ रुपये की संपत्तियों और आपराधिक मामलों से जुड़े नागरिक मामलों से संबंधित वैध शिकायतों वाले वास्तविक वादी, जिनमें अनकही पीड़ा के तहत फांसी की सजा पाए व्यक्ति और आजीवन कारावास की सजा पाए व्यक्ति और लंबे वर्षों तक कारावास में रखे गए व्यक्ति, सेवा मामलों में अनुचित विलम्ब से पीड़ित व्यक्ति-सरकारी या निजी, ऐसे मामले जिनके निपटारे की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिनमें भारी मात्रा में सार्वजनिक राजस्व या कर राशि का अनधिकृत संग्रह बंद है, हिरासत में लिए गए व्यक्ति जो हिरासत आदेशों आदि से अपनी रिहाई की उम्मीद कर रहे हैं, वे सभी न्यायालयों में जाने और अपनी शिकायतों का निवारण करने की उम्मीद के साथ वर्षों से एक लंबी कतार में खड़े

हैं, व्यस्त निकाय, हस्तक्षेप करने वाले मध्यस्थ, राहगीर या आधिकारिक हस्तक्षेपकर्ता जो व्यक्तिगत लाभ या निजी लाभ के लिए या दूसरों के प्रतिनिधि के रूप में या किसी अन्य बाहरी प्रेरणा के लिए या प्रचार की चमक के लिए जनहित याचिका का मुखौटा पहनकर अपने चेहरे बंद करने वाली कतार को तोड़ते हैं और परेशान करने वाली और तुच्छ याचिकाएं दायर करके न्यायालयों में प्रवेश करते हैं और इस प्रकार न्यायालयों का मूल्यवान समय बर्बाद करते हैं और जिसके परिणामस्वरूप न्यायालयों के दरवाजों के बाहर खड़ी कतार कभी नहीं हटती है, जो वास्तविक वादियों के मन में निराशा पैदा करती है और परिणामस्वरूप उनका हमारी न्यायिक प्रणाली के प्रशासन से विश्वास उठ जाता है।"

न्यायालय ने यह टिप्पणी करते हुए आगाह किया किः

जनहित याचिका एक ऐसा हथियार है जिसका उपयोग बहुत देखभाल और सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए और न्यायपालिका को यह देखने के लिए बेहद सावधान रहना होगा कि जनहित के सुंदर पर्दे के पीछे एक बदसूरत निजी द्वेष, निहित स्वार्थ और/या प्रचार की मांग छिपी न रहे। इसका उपयोग नागरिकों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए कानून के शस्त्रागार में एक प्रभावी हथियार के रूप में किया जाना है। जनहित याचिका के आकर्षक ब्रांड नाम का उपयोग शरारत के संदिग्ध उत्पादों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य वास्तविक सार्वजनिक गलत या सार्वजनिक चोट का निवारण करना होना चाहिए न कि प्रचार उन्मुख या व्यक्तिगत प्रतिशोध पर आधारित होना चाहिए।

XXX XXX XXX

XXX XXX XXX

न्यायालय को इस बारे में संतुष्ट होना होगा (ए) आवेदक की साख; (बी) उसके द्वारा दी गई जानकारी की प्रथमदृष्टया शुद्धता या प्रकृति; (सी) जानकारी अस्पष्ट और अनिश्चित नहीं है। जानकारी में गंभीरता और संजीदगी शामिल होनी चाहिए। न्यायालय को दो परस्पर विरोधी हितों के बीच संतुलन बनाना होगा; (i) किसी को भी दूसरों के चरित्र को धूमिल करने वाले बेतुके और लापरवाह आरोपों में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए; और (ii) सार्वजनिक शरारत से बचना और अप्रत्यक्ष उद्देश्यों, न्यायोचित कार्यकारी कार्यों के लिए हमला करने की कोशिश करने वाली शरारती याचिकाओं से बचना चाहिए। हालाँकि, ऐसे मामले में, न्यायालय उदार होने से जोखिम नहीं उठा सकता है। इसे यह देखने के लिए बेहद सावधान रहना होगा कि सार्वजनिक शिकायत के निवारण की आड़ में, यह संविधान द्वारा कार्यपालिका और विधायिका के लिए आरक्षित क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं करता है। न्यायालय को धोखेबाजों और व्यस्त निकायों या सार्वजनिक-उत्साही पवित्र पुरुषों के रूप में प्रतिरूपण करने वाले हस्तक्षेप करने वाले मध्यस्थों के साथ व्यवहार करते समय बेरहमी से कार्य करना पड़ता है। वे न्याय के योद्धाओं के रूप धारण करते हैं। वे जनहित के नाम पर काम करने का दिखावा करते हैं, हालांकि उनके पास जनता या यहां तक कि खुद के हितों की रक्षा करने का कोई इरादा नहीं है।"

177. तुच्छ और परेशान करने वाली याचिकाओं का द्वेष भारत में उत्पन्न नहीं हुआ था। भारतीय न्यायपालिका द्वारा तुच्छ और परेशान करने वाली पी. आई. आई. याचिकाओं पर अनुकरणीय लागत लगाने के संबंध में विकसित न्यायशास्त्र अन्य देशों में विकसित न्यायशास्त्र के अनुरूप है। अमेरिकी संघीय न्यायालयों और कनाडाई न्यायालयों ने भी तुच्छ माने जाने वाले जनहित के दावों पर मौद्रिक दंड लगाया है। न्यायालयों ने तुच्छ दावे दायर

करने के लिए अधिवक्ताओं पर गैर-मौद्रिक दंड भी लगाया। एवरी वुमन्स हेल्थ सेंटर सोसाइटी बनाम ब्रिजेस 54 बी.सी.एल.आर. (दूसरा संस्करण) 354 में, ब्रिटिश कोलंबिया कोर्ट ऑफ अपील ने अपीलकर्ताओं के विरुद्ध बिना किसी योग्यता के अपील करने के लिए विशेष दंड लगाया ।

178. अमेरिकी संघीय न्यायालयों ने भी तुच्छ सार्वजनिक हित के दावे करने के लिए वादी के विरुद्ध मौद्रिक दंड लगाया है। सिविल प्रक्रिया के संघीय नियमों ("एफ. आर. सी. पी".) का नियम 11 न्यायालयों को तुच्छ दावे दायर करने के लिए किसी भी पक्ष पर "उचित मंजूरी" लागू करने की अनुमति देता है। संघीय न्यायालयों ने तुच्छ जनहित के दावों पर मौद्रिक दंड लगाने के लिए इस नियम पर भरोसा किया है। उदाहरण के लिए, हैरिस बनाम मार्श 679 एफ.सप्प 1204 (E.D.N.C. 1987) में, उत्तरी कैरोलिना के पूर्वी जिले के लिए जिला न्यायालय ने दो नागरिक अधिकार वादियों पर एक तुच्छ, परेशान करने वाला, और गुणहीन योग्यता रहित रोजगार भेदभाव का दावा करने के लिए एक मौद्रिक मंजूरी लागू की। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि "संघीय न्यायालयों की बढ़ती भीड़ तथ्यात्मक रूप से निराधार और न्यायिक संसाधनों को खत्म करने वाले दावों के भारी बोझ को स्वीकार या सहन नहीं कर सकती है।" इस तरह के व्यर्थ के दावों के विरुद्ध एक निवारक के रूप में, न्यायालय ने न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए दो व्यक्तिगत नागरिक अधिकार वादी और उनके कानूनी वकील पर डॉलर 83,913.62 का जुर्माना लगाया। कनाडाई न्यायालयों और अमेरिकी संघीय न्यायालयों में मामले से पता चलता है कि तुच्छ या सार्वजनिक हित के दावों पर मौद्रिक दंड का अधिरोपण भारतीय न्यायशास्त्र के लिए अद्वितीय नहीं है।

179. इसके अतिरिक्त, अमेरिकी संघीय न्यायालयों ने तुच्छ दावे करने के लिए वकीलों पर गैर-मौद्रिक दंड लगाया है। संघीय नियम और मामला कानून इस तरह के गैर-मौद्रिक दंड को निजी दावों और सार्वजनिक हित के दावों में

समान रूप से लागू करने के लिए दरवाजे खुले रखते हैं। एफ. आर. सी. पी. का नियम 11 अतिरिक्त रूप से न्यायालयों को अपने मुवक्किलों की ओर से तुच्छ दावे दायर करने के लिए वकीलों पर "उचित मंजूरी" लागू करने की अनुमति देता है। अमेरिकी संघीय न्यायालयों ने नियम 11 के तहत तुच्छ दावे करने के लिए वकीलों पर गैर-मौद्रिक प्रतिबंध लगाए हैं।

180. उदाहरण के लिए, फ्राय बनाम पेना 199 एफ. 3डी 1332 (तालिका), 1999 डब्ल्यू. एल. 974170 में, नौवें सर्किट के लिए संयुक्त राज्य अपील न्यायालय ने जिला न्यायालय के आदेश की पुष्टि की कि एक वकील को "तुच्छ दावे करने और दबाव डालने के लिए, विभिन्न सरकारी अधिकारियों पर दुर्भावना से और उत्पीड़न के उद्देश्य से व्यक्तिगत हमले करने के लिए, और न्यायालय के प्रति स्पष्टता की कमी और अवमानना का प्रदर्शन किया।" यह न्यायिक रुख व्यावसायिक आचरण के आदर्श नियमों ("एम. आर.पी.सी") के नियम 3.1 में सन्निहित नैतिक दायित्व का समर्थन करता हैः "एक वकील किसी कार्यवाही को नहीं लाएगा या उसका बचाव नहीं करेगा, या उसमें किसी मुद्दे का दावा या विरोध नहीं करेगा, जब तक कि ऐसा करने के लिए कानून और तथ्य में कोई आधार न हो जो तुच्छ न हो।" एफ. आर. सी. पी., यू. एस. संघीय मामला कानून और एम. आर. पी. सी. मिलकर तुच्छ निजी दावों या सार्वजनिक हित के दावों को लाने के लिए वकीलों पर गैर-मौद्रिक दंड के अधिरोपण का समर्थन करते हैं।

181. महाराष्ट्र बार काउंसिल (उपरोक्त) में इस न्यायालय को आशंका थी कि कानूनी अधिस्थिति को व्यापक बनाने से मुकदमेबाजी की बाढ़ आ सकती है, लेकिन व्यापक जनहित में परिभाषा को ढीला करना भी आवश्यक है। शरारत को रोकना न्यायिक प्रणाली के प्रति दायित्व और सम्मान है।

182. एस. पी. गुप्ता (उपरोक्त) मामले में न्यायालय ने आगाह किया कि जनहित याचिका का महत्वपूर्ण क्षेत्राधिकार लोगों के एक समूह या व्यक्तियों के वर्ग के

लिए कानूनी गलतियों और कानूनी चोटों तक ही सीमित हो सकता है। इसका उपयोग व्यक्तिगत गलतियों के लिए नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि व्यक्ति हमेशा कानूनी सहायता संगठनों से निवारण की मांग कर सकते हैं। यह विवेक का विषय है न कि कानून के नियम के रूप में।

183. छेत्रीय परदुषण मुक्ति संघर्ष समिति (उपरोक्त) में इस न्यायालय ने फिर से इस बात पर जोर दिया कि अनुच्छेद 32 नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए एक महान और हितकारी सुरक्षा उपाय है। उच्च न्यायालयों को यह सुनिश्चित करना होगा कि अनुच्छेद 32 के तहत इस हथियार का किसी भी व्यक्ति या संगठन द्वारा दुरुपयोग या दुष्प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

184. जनता दल बनाम एच.एस. में चौधरी और अन्य (1992) 4 एससीसी 305, न्यायालय ने ठीक ही आगाह किया कि आधुनिक 'सामाजिक' राज्य में न्यायालयों की विस्तारित भूमिका अधिक न्यायिक जिम्मेदारी की मांग करती है। जनहित याचिका ने इस देश के करोड़ों भूखे लोगों को न्याय की नई उम्मीद दी है। न्यायालय को वास्तविक जनहित याचिका को प्रोत्साहित करना चाहिए और परोक्ष उद्देश्यों से दायर जनहित याचिका को खारिज करना चाहिए।

185. गुरुवायुर देवास्वोम प्रबंध समिति और एक अन्य बनाम सी. के. राजन और अन्य (2003) 7 एस. सी. सी. 546 में, यह दोहराया गया कि न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी प्रक्रिया का दुरुपयोग न हो और प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए, न्यायालय को उचित मामलों में निषेधाज्ञा देने से पहले सुरक्षा प्रदान आदेश पर जोर देना उचित होगा। अदालतें यह सुनिश्चित करने के लिए भारी दंड लगा सकती हैं कि न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग न हो।

186. दत्तराज नाथूजी थावरे (उपरोक्त) में इस न्यायालय ने फिर से आगाह किया और कहा कि न्यायालय को याचिका पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके क्षेत्राधिकार को लागू करने से पहले मामले में वास्तविक सार्वजनिक हित शामिल है। न्यायालय को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय द्वारा अपने व्यक्तिगत कारणों को अग्रेतर बढ़ाने या अपनी व्यक्तिगत शिकायत या द्वेष को संतुष्ट करने के लिए उसके क्षेत्राधिकार का दुरुपयोग न किया जाए। न्याय की धारा को बेईमान वादियों द्वारा प्रदूषित नहीं होने दिया जाना चाहिए।

187. नीतू (उपरोक्त) में कहा गया है कि सार्वजनिक शिकायत के निवारण की आड़ में, जनहित याचिका को संविधान द्वारा कार्यपालिका और विधायिका के लिए आरक्षित क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए।

188. मेसर्स होलिको पिक्चर्स प्राइवेट प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त) में इस न्यायालय ने कहा कि क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले न्यायाधीशों को यह देखने के लिए बेहद सावधान रहना चाहिए कि जनहित याचिका के सुंदर पर्दे के पीछे, एक बदसूरत निजी द्वेष, निहित स्वार्थ और/या प्रचार की मांग छिपी नहीं है। न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि न्यायालय की प्रक्रिया का कोई दुरुपयोग न हो।

189. जब हम वर्तमान के तथ्यों पर लौटते हैं तो निष्कर्ष स्पष्ट होता है कि यह मामला न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग का एक उत्कृष्ट मामला है। वर्तमान मामले में वकालत करने वाले वकील ने जानबूझकर न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है। उस प्रक्रिया में, उन्होंने एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद को अपमानित करने का गम्भीर प्रयास किया है। याचिकाकर्ता को यह पता होना चाहिए था कि वह याचिका में जो विवाद उठा रहा है, वह आधी सदी पहले समाप्त हो गया है और करकरे (उपरोक्त) के मामले

में नागपुर उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ के फैसले से उक्त मामले को इस न्यायालय की एक संविधान पीठ द्वारा अनुमोदित किया गया था। इस मामले में शामिल विवाद अब एकीकृत नहीं है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कानूनी स्थिति के इतने स्पष्ट प्रतिपादन के पश्चात भी समय-समय पर विभिन्न उच्च न्यायालयों में इसी तरह की बड़ी संख्या में याचिकाएं दायर की गई हैं। याचिकाकर्ता को इस तरह की तुच्छ याचिका दायर करने से बचना चाहिए था।

190. जनहित याचिका के लेबल के तहत बार के एक सदस्य द्वारा दायर याचिका के लिए प्रस्तुति में सटीकता और शुद्धता की डिग्री एक अनिवार्य शर्त है। बार के एक सदस्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वह कम से कम बुनियादी शोध तो कर ही ले कि उसके द्वारा उठाया गया मुद्दा पूर्णतः सही है या नहीं। ऐसी याचिका दायर करने वाला वकील अज्ञानता का दावा नहीं कर सकता।

191. हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम यह नहीं कह रहे हैं कि याचिकाकर्ता न्यायालय को खामियों और कमियों के कारण अपने स्वयं के फैसले की समीक्षा के लिए नहीं कह सकता है, लेकिन यह सभी प्रासंगिक मामलों को कालानुक्रमिक क्रम में सूचीबद्ध आदेश के साथ एक प्रामाणिक प्रस्तुति होनी चाहिए थी और न्यायिक मत क्या रही है इसका संक्षिप्त विवरण और ठोस और स्पष्ट अनुरोध करना चाहिए कि मौजूदा कानून पर फिर से विचार क्यों किया जाना चाहिए। दुर्भाग्य से, याचिकाकर्ता ने यह अभ्यास नहीं किया है। उच्च न्यायालय में दायर की गई याचिका कानून की प्रक्रिया का स्पष्ट दुरुपयोग है और हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि याचिका अनावश्यक विचारों के लिए दायर की गई है। याचिका में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक पद को अपमानित करने की क्षमता भी है। इस तरह की याचिका को खारिज और हतोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी याचिका दायर करने का प्रयास न करे।

192. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता पर विचार करने पर, हम राज्य द्वारा दायर अपीलों को स्वीकार करते हैं और उत्तरांचल उच्च न्यायालय में दायर 2001 की सिविल विविध रिट याचिका संख्या 689 (एम/बी) की कार्यवाही को रद्द करते हैं। हम आगे निर्देश देते हैं कि प्रतिवादी (जो उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता थे) को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के नाम पर रुपये 1,00,000/- (एक लाख रुपये) के जुर्माने का भुगतान करना होगा। प्रतिवादी द्वारा दो महीने के भीतर जुर्माने का भुगतान करना होगा। यदि दो महीने के भीतर जुर्माना जमा नहीं किया जाता है, तो उसे भूमि राजस्व अवशिष्ट के रूप में वसूल किया जाएगा।

193. हम उत्तराखंड उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध करते हैं कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के वकीलों के कल्याण कोष के नाम पर एक कोष बनाए यदि पहले से अस्तित्व में नहीं है तो। इस कोष का उपयोग उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश द्वारा बार के अध्यक्ष के परामर्श से योग्य युवा वकीलों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए किया जा सकता है।

194. हमें यह स्पष्ट करना चाहिए कि हम किसी भी तरह से जनहित याचिका को हतोत्साहित नहीं कर रहे हैं, हम इसके दुरुपयोग और दुष्प्रयोग पर अंकुश लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे अनुसार, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है और बड़ी संख्या में जनहित याचिकाओं में, न्यायालयों द्वारा पारिस्थितिकी और पर्यावरण में सुधार के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, और वनों, वन्यजीवों, समुद्री जीवन आदि के संरक्षण में मदद करने वाले निर्देश दिए गए हैं। यह न्यायालयों का बाध्यकारी कर्तव्य और दायित्व है कि वे वास्तविक जनहित याचिकाओं को प्रोत्साहित करें और जनहित में निर्देश और आदेश पारित करें जो संविधान और कानूनों के अनुरूप हैं।

195. हमारे देश में चार दशकों से अधिक समय से मौजूद जनहित याचिका का एक गौरवशाली अभिलेख है। इस न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने अपनी न्यायिक रचनात्मकता और शिल्प कौशल से संविधान की अंतर्निहित भावनाओं के अनुरूप व्यापक जनहित में कई निर्देश पारित किए हैं। पी. आई. एल. में न्यायालय के निर्देशों के कारण समाज के हाशिए पर पड़े और कमजोर वर्ग की स्थितियों में काफी सुधार हुआ है।

196. हमारे सुविचारित दृष्टिकोण में, अब यह अनिवार्य हो गया है कि वे पी. आई. एल. को सुव्यवस्थित करें।

197. हमने वर्तमान मामले के तथ्यों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। हमने कई निर्णयों में इस न्यायालय और अन्य न्यायालयों द्वारा घोषित कानून की भी जांच की है।

198. जनहित आदेश की शुद्धता और पवित्रता को बनाए रखने के लिए, निम्नलिखित निर्देश जारी करना अनिवार्य हो गया हैः-

(1) न्यायालयों को वास्तविक और प्रामाणिक जनहित याचिका को प्रोत्साहित करना चाहिए और बाहरी विचारों के लिए दायर जनहित याचिका को प्रभावी ढंग से हतोत्साहित और नियंत्रित करना चाहिए।

(2) प्रत्येक व्यक्तिगत न्यायाधीश द्वारा जनहित याचिका से निपटने के लिए अपनी प्रक्रिया तैयार करने के बजाय, प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए उचित होगा कि वह वास्तविक जनहित याचिका को प्रोत्साहित करने और अप्रत्यक्ष उद्देश्यों के साथ दायर जनहित याचिका को हतोत्साहित करने के लिए उचित रूप से नियम बनाए। नतीजतन, हम अनुरोध करते हैं कि जिन उच्च न्यायालयों ने अभी तक नियम नहीं बनाए हैं, उन्हें तीन महीने के भीतर नियम बनाने चाहिए। प्रत्येक उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि उच्च न्यायालय द्वारा तैयार

किए गए नियमों की एक प्रति इसके तुरंत बाद इस न्यायालय के सेक्रेटरी जनरल को भेजी जाए।

(3) न्यायालयों को पी. आई. एल. पर विचार करने से पहले याचिकाकर्ता की साख को प्रथमदृष्टया सत्यापित करना चाहिए।

(4) न्यायालय को जनहित याचिका पर विचार करने से पहले याचिका की सामग्री की शुद्धता के बारे में संतुष्ट होना चाहिए।

(5) न्यायालय को पूरी तरह से संतुष्ट होना चाहिए कि याचिका पर विचार करने से पहले पर्याप्त सार्वजनिक हित शामिल है।

(6) न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिस याचिका में व्यापक जनहित, गंभीरता और तात्कालिकता शामिल है, उसे अन्य याचिकाओं पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

(7) न्यायालयों को जनहित याचिका पर विचार करने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जनहित याचिका का उद्देश्य वास्तविक सार्वजनिक नुकसान या सार्वजनिक चोट का निवारण करना है। न्यायालय को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जनहित याचिका दायर करने के पीछे कोई व्यक्तिगत लाभ, निजी उद्देश्य या अप्रत्यक्ष उद्देश्य न हो।

(8) न्यायालय को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यस्त निकायों द्वारा बाहरी और गलत उद्देश्यों के लिए दायर याचिकाओं को अनुकरणीय दंडो को लागू करके या तुच्छ याचिकाओं और बाहरी विचारों के लिए दायर याचिकाओं पर अंकुश लगाने के लिए समान नए तरीकों को अपनाकर हतोत्साहित किया जाना चाहिए।

199. इस निर्णय की प्रतियां एक सप्ताह के भीतर सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरलों को भेजी जाएं।

200. ये अपीलें हमारे आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए 03.05.2010 को सूचीबद्ध की गई हैं।

जे.----------

(दलवीर भंडारी)

जे.----------

(डॉ. मुकुंदकम शर्मा)

नई दिल्ली;
18 जनवरी, 2010.